सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 247 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 20 जून 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी कुछ जगह फट सकतें हैं बादल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग समेत कई जिलों में मानसून एक्टिव है। मानसून के सक्रिय होने से सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से स्थानीय नदियां, नहर, नाले उफान पर है। कई जिलों में पूरी रात रूक-रूककर बारिश हुई। साथ ही जशपुर और बलरामपुर के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है।

इधर, राजधानी रायपुर में भी पिछले दो दिनों से बादल छाये हुये हैं। हालांकि लोग उमस वाली गर्मी से परेशान जरुर है। आसमान में बदली है, लेकिन पानी नहीं गिरने से लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हैं। ऐसा ही हाल दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी का है। इन जिलों में भी मौसम तो बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान सरगुजा संभाग में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है। जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर में आज आंधी-तूफान और बिजली के साथ हैवी रैन हो सकती है।

दुर्घटना में आरक्षक की मौत, परिवार को मिला एक करोड़ का चेक

भिलाई। पुलिस सेलरी पैकेज (पीएसपी) दुर्घटना मृत्यु दावा के अंतर्गत दुर्घटना में मृत आरक्षक उपेन्द्र कुमार तिवारी की नामिनी उनकी माता चंद्रकांति तिवारी को 1 करोड़ रुपए का चेक मिला। एसएसपी विजय अग्रवाल, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक रूपक मंडल सेक्टर-1 भिलाई तथा एसबीआई शाखा गंजपारा के शाखा प्रबंधक राहुल मोदी के द्वारा आरक्षक की माता को 1 करोड़ रूपये का चेक सौंपा गया।

आरक्षक उपेन्द्र कुमार तिवारी, पुलिस विभाग जिला दुर्ग में कार्यरत थे, जिनका 26 दिसंबर 2024 को सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया। पुलिस विभाग द्वारा एसबीआई से पुलिस सेलरी पैकेज के अंतर्गत सकल बीमा कवरेज का एमओयू किया गया है, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर शुक्रवार को उनकी नामिनी माताजी चंद्रकांति तिवारी को मिला 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस सेलरी पैकेज के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता या स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर पृथक-पृथक राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय गृहमंत्री शाह के दौरे से पहले एक और मुठभेड़, दो ढेर, महिला नक्सली का शव बरामद

सुरक्षाबलों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी, बढ़ सकते हैं मारे गए नक्सलियों के आंकड़े

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कांकेर जिले में शुक्रवार को सुबह से सुरक्षाबलों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं एक महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। मौके से सुरक्षाबलों ने हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना छोटेबेठिया कोटरी नदी पार के ग्राम आमाटोला और कलपर के मध्य जंगल पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को माओवादियों की उपस्थित की सूचना मिली थी। जिसके बाद सर्चिंग अभियान पर डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी रवाना हुई। जैसे ही जवान मौके पर पहुंचे फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की फायरिंग कमजोर पड़ने लगी। मुठभेड़ में एक महिला माओवादी का शव और हथियार बरामद हुआ है। घटना स्थल पर अभी भी रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं जवानों ने सर्चिंग अभियान जारी रखा है।

कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम को छोटे बेठिया इलाके के आमाटोला और कलपर के बीच जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर डीआरजी और बीएसएफकी संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। मुठभेड़ वाला इलाका माड़ से सटा है। इसी इलाके में जवानों ने सबसे ज्यादा नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम कलपर में 2024 में हुई मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सली मारे गए थे, जिसमें कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल थे। पुलिस की सयुक्त टीम ने एक बार फिर इसी इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया है।

2 दिन पहले मारे गए थे 3 बड़े नक्सली लीडर

बता दें दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारेडपल्ली में हुई मुठभेड़ में ग्रेहाउंड्स फोर्स ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर गजरला रवि, अरुणा समेत 3 बड़े कैडर्स को मार गिराया। गजरला 40 लाख का इनामी था। वहीं एनकाउंटर में मारी गई अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर एसजेडसीएम थी और नक्सली लीडर चलपति की पत्नी है। इस पर 20 लाख का इनाम था। आंध्रप्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू जिले के एसपी अमित बरदार ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए इसकी जानकारी दी थी।

22 जून को दो दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह, रायपुर में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की रखेंगे नींव, बस्तर में जवानों से भी मिलेंगे

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दो दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वह नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राज्य की फॉरेंसिक लैब की आधारशिला रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह बस्तर क्षेत्र में सुरक्षाबलों के एक शिविर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नक्सल विरोधी अभियानों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने नवा रायपुर में एनएफएसयू के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिसे केंद्र की तरफसे लगभग चार सौ करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। राज्य फोरेंसिक लैब एनएफएसयू के करीब ही छह से सात एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि शाह 23 जून को बस्तर क्षेत्र में सुरक्षाबलों के एक शिविर का दौरा करेंगे। वह नक्सली विस्फोट की घटना में बलिदान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। वे 9 जून को सुकमा जिले में नक्सलियों के लगाए प्रेशर बम की चपेट में आकर शहीद हो गए थे।

शाह का दावा- मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया होगा

बता दें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है। उन्होंने ये बात अगस्त 2024 में में बस्तर दौरे के दौरान कही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सरेंडर पॉलिसी, हमले और विकास के दम पर नक्सलियों को खत्म किया जाएगा। शाह का यह दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि नक्सलियों के गढ़ फोर्सेस लगातार अभियान चला रही है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विभाग ने जब्त किए 9 वाहन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रायगढ़ जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग के उपसंचालक राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था। इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप संचालक मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में राजा जैसा हत्याकांड : पत्नी ने मुर्गा-भात में जहर मिलाकर पति को खिलाया

पसंद नहीं था पति, शादी के एक माह बाद कर दी हत्या

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में भी मेरठ के राजा रघुवंशी जैसा एक हत्याकांड सामने आया है। यहां के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में एक नव विवाहिता ने अपने पति को जहर देकर मार दिया। पति के लिए मुर्गा-भात बनाया और उसमें जगर मिलाकर खिला दिया। खास बात यह है कि जहर भी उसने पति से ही खरीदवाया था। पति एक बार भी समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी इतना बड़ा षड़यंत्र रच रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपिया पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार हत्या की यह वारदात बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रंका थाना क्षेत्र के बाहोकुदर गांव की है। पुलिस के अनुसार, 11 मई 2025 को बुधनाथ सिंह (22) की शादी रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव की रहने वाली सुनीता सिंह से हुई थी। शादी के दूसरे दिन नवविवाहिता अपने मायके लौट आई। परिवार वालों को उसने बताया कि उसे उसका पति पसंद नहीं है और वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। इसके बात पंचायत व परिजनों की समझाइश के बाद 5 जून को वह ससुराल वापस पहुंची।

बाजार में पति से खरीदवाया कीटनाशक

सुनिता ससुराल तो पहुंच गई लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पति को मार देगी। 14 जून को पति-पत्नी बाजार गए थे। इस दौरान सुनीता ने फसल में कीड़े मारने के बहाने पति से कीटनाशक खरीदवाया। इसके बाद उसने दो बार खाने में जहर मिलाकर पति को मारने की कोशिश की, लेकिन बुधनाथ ने दोनों बार खाना खाने से मना कर दिया इसके कारण दो बार बच गया।

तीसरी बार मुर्गा-भात ने ले ली जान

दो बार बचने के बाद बुधनाथ तीसरी बार बच नहीं पाया। 15 जून की रात उसकी पत्नी सुनीता ने मुर्गा-भात बनाया और उसमें कीटनाशक मिला दिया। रात को बुधराम ने पूरा खाना खा लिया इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके कुछ ही देर बाद बुधनाथ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजा। पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

सास पर लगाया आरोप, लेकिन पकड़ाया झूठ

जांच दौरान पुलिस को पत्नी पर ही जहर देने का शक था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सुनीता ने नई कहानी सुनाई और सास पर ही जहर देने का आरोप लगा दिया। उसका कहना था कि सास उसे मारना चाहती थी, लेकिन गलती से जहर मिला खाना बेटे को दे दिया। हालांकि सुनीता का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने बुधराम पसंद नहीं था और अपने परिवार वालों को भी यह बात बताई थी इसके बाद उसकी शादी कर दी गई।

फर्जी जाति प्रमाणपत्र से आरक्षित सीट से बनी जिला पंचायत अध्यक्ष

रिटायर आईएएस की बेटी पर फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाने का आरोप, जांच कमेटी गठित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा और आरक्षित सीट से जीतकर अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुई।

शिकायत के अनुसार, नम्रता जैन द्वारा प्रस्तुत एसटी प्रमाण पत्र 26 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था, लेकिन उसकी वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप यह भी है कि यह प्रमाण पत्र तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर चंद्रिका प्रसाद बघेल द्वारा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया गया था, जो अब भ्रष्टाचार के दायरे में आ गया है।

ओडिशा में जन्म जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से बनाया

शिकायत में कहा गया है कि नम्रता सिंह के पिता स्व. नारायण सिंह ओडिशा के मूल निवासी थे। वे छत्तीसगढ़ कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। 1950 से पहले परिवार का छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। निवास प्रमाण, न राजस्व रिकॉर्ड, और न ही ग्राम सभा की अनुशंसा। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, एक राज्य की अनुसूचित जनजाति पहचान दूसरे राज्य में मान्य नहीं होती। यानी ओडिशा की जनजातीय पहचान छत्तीसगढ़ में वैध नहीं है। फिर भी प्रमाण पत्र जारी होना गंभीर सवाल खड़ा करता है।

शिकायत के बाद एसडीएम ने बनाई जांच कमेटी

एसडीएम मोहला द्वारा 26 मई 2025 को जारी पत्र में नम्रता सिंह जाति केस में जांच समिति के गठन की पुष्टि की गई है। शिकायतकर्ता विवेक सिंह ने मांग की है कि जांच 15 दिनों के भीतर पूरी कर दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही शिकायत में मांग की गई है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत अध्यक्ष को पदमुक्त किया जाए।

जब ऐसी बातों से सत्ता चलने लगे

श्रीकंचनपथ

एक नेता जी ने भविष्यवाणी की है कि 2047 तक देश दुनिया के टॉप पर होगा। मतलब 22 साल और इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, वक्त तो लगता है। पर नेता जी ने यह भी कहा कि एक दिन आएगा जब देश के लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म महसूस होगी। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं है। वैसे बोलने को ज्यादा कुछ नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां 459 से अधिक बोलियां और भाषाएं हैं। इनमें से दक्षिण भारतीय भाषाओं और बोलियों को बोलने समझने में मध्य भारत, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के लोगों को दिक्कत होती है। इसी तरह दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर की भाषा-बोली में दिक्कत होती है। इसीलिए देश में एक सम्पर्क भाषा की जरूरत हमेशा नहीं है। अधिकांश देश के लिए हिन्दी ही सम्पर्क भाषा है। पर जहां दिक्कत ज्यादा है वहां अंग्रेजी ही कामचलाऊ सम्पर्क भाषा बन जाती है। यह इसलिए आज उपयोग में आने वाले अधिकांश शब्द अंग्रेजी के ही होते हैं। इन शब्दों का उपयोग तेलुगु, तमिल, मलयाली, तमिल, बंगाली, मराठी, ओड़िया, आदि सभी भाषाओं के बोलने वाले करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी को अंग्रेजी से कोई खास प्यार है। उपलब्धता और उपयोग की सरलता के कारण इसे लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर नेताजी ने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब साफ है कि देश की जनता इसी तरह की बातों से खुश होती है, आह्लादित होती है। इन्हीं का बड़ा भाई विदेश में जाकर चार शब्द अंग्रेजी का बोल आएगा तो भी तालियां बजाई जाएंगी। जिन नेताओं के भी बाल बच्चे हैं, वो सबके सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। जितने भी सरकारी अफसर हैं उनके बच्चे भी इसी नक्शे कदम पर हैं। आज तो स्थिति यह है कि लोगों ने घर पर भी मातृभाषा बोलनी छोड़ी दी है। इससे बच्चे की अंग्रेजी की फ्लूएंसी खराब हो जाती है। इसलिए पढ़े लिखे माता-पिता अपने बच्चों से घर पर भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हमारी पीढ़ी तक लोगों के घर में आंचलिक पत्रिकाएं आती थीं। जिन्हें लिखने पढ़ने का शौक होता, इन्हें पढ़कर भी भाषा सीख जाता। पर अब कुछ भी लिख कर नहीं आता। चिट्ठियों की जगह फोन और वीडियो कॉल्स ने ले ली है। इसलिए भी मातृभाषा को पढ़ना जरूरी नहीं रहा। ये कोई षड़यंत्र नहीं बल्कि वक्त की और भविष्य की जरूरत है। फिर भी नेता बकवास करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जनता सुनती है और तालियां बजाती है। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई अंग्रेजी को, अंग्रेजों को गाली दे, अंग्रेजियत की मिट्टी पलीद करे। अंग्रेजी पर शर्मिंदा होने वाली बात भी इसी तरह का एक शिगूफा है।

संपादकीय

परमाणु बम सुरक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं

वर्तमान में परमाणुशक्ति संपन्न जितने देश हैं,उन्होंने परमाणु बम बनाया है तो अपनी सुरक्षा के लिए। परमाणु बम होने पर देश मान लेता है कि उस पर कोई देश हमला करने के पहले सौ बार सोचेगा।सब जानते हैं कि परमाणु बम महाविनाशकारी होता है। उसका इस्तेमाल करने पर लाखों लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए जितने परमाणुशक्ति संपन्न देश हैं, उनका उपयोग उन्होंने युद्ध की स्थिति होने पर नहीं किया है। परमाणु बम उपयोग करने के लिए नहीं है, वह देश की सुरक्षा के लिए है। दो परमाणुशक्ति संपन्न देश एक दूसरे पर हमला इसलिए नहीं करते हैं कि दोनों के पास परमाणुबम है और जानते हैं कि इसका उपयोग करने का मतलब होगा दोनों देशों में महाविनाश। परमाणु बम के उपयोग का मतलब है परस्पर महाविनाश।

वर्तमान में ईरान व इजराइल के बीच युध्द इसलिए हो रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इजराइल उसे नहीं बनाने देना चाहता है। अमरीकी सहित दुनिया के बड़े देश भी नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए क्योंकि वह प. एशिया में अस्थिरता का स्त्रोत है। वहां के सबसे बड़े नेता ही यह कहते हैं कि यहुदियों का नामानिशा मिटा दिया जाएगा। वह अमरीका व इजराइल को शैतान कहते हैं और उसे मारना चाहते हैं। यही वजह है कि अब कोई नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम होना चाहिए क्योंकि बम उसके पास हुए तो उसका उपयोग इजराइल व अमरीका पर पहले करेगा। जी-7 की बैठक में इस बात को दोहराया गया है कि ईरान के पार परमाणु बम नहीं होना चाहिए और हम सब इजराइल के साथ हैं। यानी इजराइल ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देने के लिए जो कुछ कर रहा है, सब उसका समर्थन करते हैं।

> *परमाणु बम बना लेना एक उपलब्धि तो है लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को निभाने की योग्यता सभी देशों में नहीं होती है, इसलिए सभी देश परमाणु बम तो बनाना चाहते हैं लेकिन विश्व के शक्तिशाली देश, उसे इस बात की इजाजत नहीं देते हैं क्योंकि वह जानते है कि इस देश का नेतृत्व इस लायक नहीं है कि यह परमाणु बम बनाकर उसका उपयोग सुरक्षा के लिए करेगा। वह किसी पर भी परमाणु बम का उपयोग कर सकता है, इसलिए विश्व के बड़े देश किसी देश को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देते हैं। ईरान ऐसा ही देश है, जो परमाणु ऊर्जा के नाम पर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और गुपचुप परमाणु बम बनाने की तैयारी करने लगा। अमरीका सहित बड़े देशों को पता चला तो उन्होंने ईरान पर कई तरह का बैन लगा दिया कि वह परमाणु बम न बना सके। इसके बाद भी ईरान गुपचुप परमाणु बम बनाने में जुटा रहा। इजराइल का इस बात का पता चलने पर की ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है तो उसने कई परमाणु वैज्ञानिकों का मार दिया है, परमाणु बम बनाने का जहां काम किया जा रहा है उस जगह को नष्ट करने का प्रयास किया है।*

ईरान की इजराइल को खत्म करने देने की कितनी तीव्र इच्छा है इसका पता इस बात से चलता है कि ईरान ने दावा किया कि अगर इजराइल हम पर परमाणु बम से हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा।अभी तक इजराइल ने कभी नहीं कहा है कि वह ईरान पर परमाणु बम से हमला करेगा लेकिन ईरान सोच रहा है और पाकिस्तान से मदद की उम्मीद कर रहा है। उसकी उम्मीद निराधार भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल के हमले पर ईरान के साथ खडे होने की बात कही थी। सभी इस्लामिक देशों के एकजुट होने की बात कही थी। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो अमरीका की वजह से। वह चुपके से ईरान की मदद की बात तो कर सकता है लेकिन खुले तौर पर नहीं कर सकता। यही वजह है ईरान के बयान पर पाकिस्तान को कहना पड़ा कि उसने ऐसा कुछ ईरान से नहीं कहा है। ईरान समझ रहा था कि एक इस्लामिक देश का परमाणु बम सभी इस्लामिक देशों का है, लेकिन पाकिस्तान को कहना पड़ा कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का परमाणु बम पाकिस्तान का ही है। सभी इस्लामिक देशों का नहीं है और उनके लिए उपयोग भी नहीं किया जा सकता।

भारत में तकनीकी वस्त्र का बढ़ता दायरा: एनटीटीएम और पीएलआई ने बदली तस्वीर

गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री

कुछ साल पहले, तकनीकी वस्त्रों को एक सीमित खंड के रूप में देखा जाता था। इसका दायरा सीमित था, इसमें कम निवेश किया जाता था और आयात पर यह बहुत अधिक निर्भर था लेकिन आज, यह भारत के औद्योगिक परिवर्तन के केंद्र में हैं। यह बदलाव आकस्मिक नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप अपनाई गई रणनीति, नीतिगत दूरदर्शिता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का परिणाम है। चाहे कोविड-19 संकट के दौरान पीपीई उत्पादन को बढ़ाना हो, स्वदेशी सुरक्षात्मक गियर के साथ सशस्त्र बलों को सुसज्जित करना हो या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करना हो, तकनीकी वस्त्रों ने राष्ट्रीय तैयारियों और औद्योगिक प्रगति के कारक के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है।

श्रेष्ठ से रणनीतिक तक: नीतिगत अनिवार्यता

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की समीक्षा बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया, जब मुझे इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ से बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने कार्बन फाइबर, अल्ट्रा-हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन और नायलॉन 66 जैसे उच्च प्रदर्शन वाले एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित किया। उनका संदेश स्पष्ट था: भारत को इस क्षेत्र में दूसरों पर निर्भरता को कम करने के लिए और हमारी वैज्ञानिक उन्नति के अगले स्तर के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इन क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। इस बातचीत के दौरान प्रयोगशालाओं से लेकर लॉन्चपैड तक भारत की विकास गाथा में तकनीकी वस्त्रों के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया गया।

लैब से लेकर लॉन्चपैड व युद्ध के मैदान तक

रक्षा क्षेत्र ने भी इस परिवर्तन के रणनीतिक मूल्य को महसूस करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए हाल ही में हमारे सशस्त्र बलों द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर को लें, जहां सुरक्षात्मक कपड़ों और बैलिस्टिक गियर से लेकर छलावरण वाले कपड़ों और रासायनिक-जैविक सुरक्षा सूट तक तकनीकी वस्त्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि हमने घरेलू क्षमता निर्माण में जल्दी निवेश करना शुरू कर दिया था, इसलिए आज हम अपने रक्षा क्षेत्र को न केवल जनशक्ति के साथ, बल्कि वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली सामग्री के साथ मदद पहुंचाने में सक्षम हैं, जिसे भारतीय धरती पर विकसित और निर्मित किया गया है।

तकनीकी वस्त्रों को समझें

तकनीकी वस्त्र वे विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं, जो सौंदर्य की बजाय कार्यक्षमता के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें अक्सर जीवन रक्षक या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के तहत कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें बुलेट-प्रतिरोधी जैकेट, अग्निरोधी वर्दी, सर्जिकल गाउन, किसानों के लिए एंटी-बैक्टीरियल शीट, सड़क-सुदृढ़ीकरण जियो-ग्रिड और बहुत कुछ शामिल हैं। यह क्षेत्र जियोटेक, मेडिटेक, प्रोटेक, एग्रोटेक और बिल्डटेक सहित 12 प्रमुख खंडों में फैला हुआ है। 2024 तक, भारत के तकनीकी वस्त्र बाजार का मूल्य 26 बिलियन अमरीकी डॉलर था। हम 2030 तक 40-45 बिलियन अमरीकी डॉलर को छूने की राह पर हैं, जो 10-12 प्रतिशत की आकर्षक वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर तकनीकी वस्त्र, कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत है जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 11 प्रतिशत है। हालांकि सही दिशा में प्रयास करने से हम इस अंतर को तेज़ी से कम कर रहे हैं।

विकास को गति देने के लिए प्रमुख सरकारी पहल

इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए, भारत सरकार ने दो प्रमुख पहलों- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) और वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से कुल 12,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया है। ये कार्यक्रम अलग-अलग काम करने के बजाय, साथ मिलकर, भारत को तकनीकी वस्त्रों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदल रहे हैं। एनटीटीएम के तहत, हम अनुसंधान और नवाचार में केंद्रित निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। 510 करोड़ रुपए की सरकारी मदद के साथ कुल 168 उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से कई पहले ही प्रयोगशाला से बाजार में आ चुकी हैं जिनमें फायर एंट्री सूट का विकास और भू-वस्त्रों के लिए परिपत्र बुनाई तकनीक शामिल हैं।

एनटीटीएम: नवाचार को बढ़ावा देना और कौशल प्रदान करना

आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से प्रेरित, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नवाचार और कौशल विकास के लिए मजबूत नींव रख रहा है। वहीं 17 स्टार्टअप को ग्रेट (तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान) योजना के तहत सहायता मिली है। 2,000 से अधिक छात्र 41 शीर्ष संस्थानों में तकनीकी वस्त्र पाठ्यक्रम कर रहे हैं जो 16 उद्योग-आधारित कौशल मॉड्यूल द्वारा समर्थित हैं और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को आकार दे रहे हैं।

मांग पैदा करना, वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना

मुख्य स्तंभ के रूप में बाजार विकास के साथ, एनटीटीएम घरेलू स्तर पर अपनाने के साथ-साथ वैश्विक पहुंच का भी विस्तार कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में 73 तकनीकी वस्त्र सामग्रियों के अनिवार्य उपयोग ने उन्हें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया है। भारत टेक्स 2025 सहित 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों ने भारत की स्थिति को मजबूती दी है। इस बीच, कुल मिलाकर मानव निर्मित कपड़ा निर्यात 2020-21 में 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। वहीं आयात में कमी से बढ़ती आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेत मिलता है।

प्रदर्शन को नीति से जोड़ना: पीएलआई ढांचा

निजी क्षेत्र में, प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाता है। जो लोग लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने और देश के रोजगार परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यही सिद्धांत अब उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से हमारी औद्योगिक नीति को दर्शाता है। यानी प्रोत्साहन अब सब्सिडी नहीं, बल्कि प्रदर्शन से जुड़े पुरस्कार हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, विनिर्माण को एक मिशन की तरह माना जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट मीट्रिक, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और विकासोन्मुख मानसिकता हो। एनटीटीएम और पीएलआई साथ मिलकर एक दोहरे इंजन का काम करते हैं: जहां एनटीटीएम अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नींव रखता है, पीएलआई योजना विकास को गति दे रही है। योजना के तहत चयनित 80 कंपनियों में से आधे से अधिक (ठीक 56.75 प्रतिशत) तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह उद्योग के आत्मविश्वास का एक मजबूत संकेतक है। इस समर्थन की बदौलत, हमने 7,343 करोड़ रुपए का नया निवेश देखा है जिससे 4,648 करोड़ रुपए का प्रभावशाली कारोबार और 538 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कपड़ा मंत्रालय ने सक्रिय कदम उठाए हैं। हमने तीन मौकों यानी जून 2023, अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 पर तकनीकी वस्त्रों के लिए एचएसएन कोड जारी किए और सीमा शुल्क और अनुपालन को स्पष्ट करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए। फरवरी 2025 में हुए एक महत्वपूर्ण संशोधन के कारण कुल 54 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन संवितरण समय से पहले संभव हुआ। हमारी महत्वाकांक्षाएं, घरेलू सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर, यह योजना भारत को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अग्रणी वैश्विक कपड़ा निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार कर रही है।

अब तक का प्रभाव

हमारी संयुक्त पहलों का असर पहले से ही दिखाई दे रहा है। तकनीकी वस्त्रों के लिए भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। मार्च 2025 तक, हमने 5,218 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है और 8,500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है। अकेले तकनीकी वस्त्रों ने 3,242 करोड़ रुपए का कारोबार किया है जिसमें 217 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी रणनीति काम कर रही है।

सतत् और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर

स्थिरता और चक्रीयता भारत की तकनीकी वस्त्र रणनीति के केंद्र में हैं। जूट, भांग, रेमी, कपास, रेशम और यहां तक कि मिल्कवीड जैसे प्राकृतिक रेशों को उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हुए हमारे किसानों और उद्योगों को सशक्त बना रहे हैं। प्रकृति-आधारित समाधान, शक्तिशाली उपाय के रूप में उभर रहे हैं जो पारंपरिक रेशों के साथ नवाचार को मिलाते हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीरी पश्मीना से निकलने वाले कचरे का उपयोग अब इंसुलेशन बनाने में किया जाता है, कपास और रेशम का उपयोग घाव की ड्रेसिंग और ऊतक इंजीनियरिंग में किया जा रहा है और रेशम का उपयोग 3डी प्रिंटिंग में किया जा रहा है। जूट बायोडिग्रेडेबल मेडिकल इम्प्लांट, ऑटोमोबाइल के लिए हल्के कंपोजिट फाइबर, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और टिकाऊ फर्नीचर बनाने में सक्षम है। साथ ही, हम घरेलू मशीनरी विनिर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके तहत 68,000 करोड़ रुपए मूल्य के सामान के उत्पादन के लिए 25 परियोजनाएं चल रही हैं। इनसे निर्यात में 6,700 करोड़ रुपए का योगदान मिलने की उम्मीद है जो वास्तव में आत्मनिर्भर और टिकाऊ औद्योगिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत न केवल वैश्विक तकनीकी वस्त्र आंदोलन में भाग ले रहा है, हम इसका नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। एनटीटीएम और पीएलआई की संयुक्त शक्ति के साथ, हम नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, निर्यात को मजबूत कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती ला रहे हैं। हमारे रक्षा और कृषि क्षेत्रों को मदद देने से लेकर बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तक, तकनीकी वस्त्र भारत के लिए एक नई औद्योगिक पहचान को आकार दे रहे हैं और यह केवल एक शुरुआत है।

जनगणना में स्व-गणना की सुविधा डिजिटल होगी

प्रमोद भार्गव

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है। कोविड महामारी के कारण 2021 में होने वाली यह जनगणना अब शुरू होगी। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जातिवार जनगणना कराने की मांग कर रहा था। अचानक मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला लेकर पूरे विपक्ष को चौंका दिया। क्योंकि अब यह मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

साथ ही सभी वर्गों की प्रमुख जातियों के साथ उपजातियों की जनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि सैद्धांतिक रूप से जातिगत गणना कराना उचित था या नहीं? ई-बाजार, ई-आवेदन, ई-रेल व बस में आरक्षण ई-भुगतान के बाद अब ई-जनगणन यानी डिजिटल गिनती होगी। इस गिनती में जाति की गिनती भी साथ-साथ होगी। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों ही डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे। हर जन्म के बाद डिजिटल जनगणना खुद ही अद्यतन हो जाएगी और जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम खुद ही डाटा से डिलीट हो जाएगा। सेंसर रजिस्टर यानी जनगणना में बच्चे के जन्म माता-पिता, जाति और जन्म स्थान की जानकारी समेत 16 भाशाओं में 36 प्रश्नों के उत्तर दर्ज हो जाएंगे।

बालक जब 18 साल का होगा तो खुद ही उसका नाम चुनाव आयोग के पास चला जाएगा, नतीजतन उसका मतदाता पहचान पत्र बनने के साथ मतदाता सूची में भी नाम स्वमेव दर्ज हो जाएगा। फिर जब किसी की मौत हो जाएगी तो ऑनलाइन जनगणना के डाटा से उस शख्स का नाम खुद ही डिलीट भी हो जाएगा। इस तरह से जनगणना का डाटा हमेशा खुद अद्यतन होता रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर करीब 12000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिजिटल जनगणना की घोषणा 1 फरवरी 2021 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।

जनगणना-2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं। जनगणना (संशोधन)-2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारूप भर सकता है। इसके लिए पूर्व नियमों में इलेक्ट्रॉनिक फार्म शब्द जोड़ा गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा दो की उप धारा (एक) के खंड आर में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैग्नेटिक, कंप्यूटर जनित माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी या संग्रहित की गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा। यानी एनरायड मोबाइल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी, जो कि आजकल घर-घर में उपलब्ध है। इस ऑनलाइन प्रविष्टि के अलावा घर-घर जाकर भी जनगणना की जाएगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन प्रयोग अद्वितीय है। लेकिन देश की जनता के स्थायी और निंरतर गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत अब जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए। गिनती के विकेर्द्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। इस लेख में प्रस्तुत की जाने वाली जनगणना की यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तेज भागती यांत्रिक व कंप्यूटरीकृत जिदंगी में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार व संरचना का दस साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता? वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैगिंक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर मे परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिपर्तन लाएं?

जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदार्थों व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के पर्याप्त उपायों के इजाफे के पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाया जाता है। 2028 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिषत सीटें आरक्षित रहेंगी। जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश व दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात सौ करोड़ हो चुकी है। 2050 में यह आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस आबादी का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा महज नौ देशों चीन, भारत, अमेरिका, पकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया और तंजानिया में होगा। परिवार नियोजन के तमाम उपायों के बावजूद दुनिया में प्रति महिला सकल प्रजनन दर 2.5 शिशु है, 2050 में यह दर घटकर 2.1 प्रति महिला प्रति शिशु रह जाने की उम्मीद है।

धरती पर जितनी तेजी से मानव समुदायों की आबादी उन्नसवीं सदी में बढ़ी है, उतनी तेजी से बढ़ोतरी पहले कभी दर्ज नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक ईसवी सन एक में धरती पर कुल आबादी लगभग तीस करोड़ थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत में दुनिया की जनसंख्या एक अरब के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। इन शताब्दियों में जन्म दर की मात्रा अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर बेहद मंदी थी। प्रकृति पर निर्भर गर्भ निरोधकों से दूर और उपचार की आसान व सुलभ पद्धतियों से अनजान स्त्री-पुरूष बच्चे तो खूब पैदा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मर जाया करते थे। बीमारियों की पहचान और उपचार से नियंत्रण के चलते बीसवीं शताब्दी के पहले ही तीन दशको में यह आबादी दोगुनी होकर करीब पौने दो अरब के आंकड़े को छू गई थी।

भारत की जनसंख्या 1901 में 23,83,96,327 थी। आजादी के साल 1947 में यह आबादी 34.2 करोड़ हो गई थी। 1947 से 1981 के बीच भारतीय आबादी की दर में ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई और आबादी 68.4 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करने वाले विशेषज्ञो का मानना है कि भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ 60 लाख आबादी बड़ जाती हैं। इस दर के अनुसार हमें अपने देश की करीब एक अरब 40 करोड़ लोगों की एक निशचित जनसंख्या प्रारूप में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों और संसाधनों के समतुल्य आर्थिक व रोजगारमूलक विकास का खाका खींचा जा सके। जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे उसका मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है।

हरेक दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब 34 लाख कर्मचारी जुटते हैं। डिजिटल डिवाइस से लैस 1.3 लाख जनगणना अधिकारी भी रहेंगे। छह लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी-दल को उसके स्थनीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरांचल गांव में भेज दिया जाता हैं। ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लोग होते हैं। बीते कुछ सालों में आधुनिक व आर्थिक विकास की अवधारणा के चलते इन्हीं जाति समूह के करीब चार करोड़ लोग विस्थापन के दायरे में हैं। इनसे रोशन गांव तो अब बेचिराग हैं, लेकिन इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहां है, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुशकिल होता है ?

जनगणना की विधि का हो विकेंद्रीकरण

जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदला जाकर एक ऐसे स्वरूप में तब्दील किया जाए, जिससे इसकी गिनती में निरंतरता बनी रहे। इसके लिए न भारी भरकम संस्थागत ढांचे की जरूरत है और न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती की केन्द्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेन्द्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। देश की सबसे छोटी राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खण्ड व जिला स्तर तक है। हमें करना सिर्फ इतना है कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रखनी है। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंप्युटर में फीड जनसंख्या प्रारूप पर भी दर्ज हो। जिन ग्राम पंचायतों में इसे जनसंख्या संबंधी वेबसाइट से जोड़कर इन आंकड़ो का पंजीयन सीधे अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है। जैसा कि अब ऑनलाइन माध्यमों से अपनी गिनती दर्ज करा सकेंगे।

परिवार को इकाई मानकर सरपंच, सचिव ओर पटवारी को यह जवाबदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नामकरण व अन्य जानकारियां जनसंख्या प्रारूप के अनुसार इन पंजियों में दर्ज करें। इस गिनती को सचित्र भी किया जा सकता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर का प्रत्येक व्यक्ति एक दुसरे को बखूबी जानते हैं इसलिए इस गिनती में चित्र व नाम के स्तर पर भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। जैसा कि मतदाता सूचियों और मतदाता परिचय-पत्र में हो जाती हैं। गिनती की इस प्रक्रिया से कोई वंचित भी नहीं रहेगा। क्योंकि जनगणना किए जाने वाले जन और जनगणना करने वाले लोग स्थानीय हैं। गांव में किसी भी शिशु के पैदा होने की जानकारी और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है, अत: इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत पर एकत्रित होने वाली यह जानकारी प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को विकासखण्ड स्तर पर पहुंचाई जाकर पंजी की एक प्रति विकासखण्ड कार्यालय में रखी जाए और इसे आधार बनाकर इसका तत्काल कंप्यूटरीकरण किया जाए। जिले के सभी विकास खंडों की यह जानकारी जिला स्तर पर बुलाई जाए और यहां इसका एकीकरण किया जाकर इस गिनती को कंप्यूटर में फीड किया जाए। इस तरह से सभी विकासखण्डो के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक माह होती रहेगी। जिलाबार गणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर सांख्यकीय कार्यालय में इकट्ठा कर प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा भी प्रत्येक माह सामने आता रहेगा। प्रदेशवार जनसंख्या के आंकडो को देश की राजधानी में जनसंख्या कार्यालय में संग्रहीत कर प्रत्येक माह देश की जनगणना का वैज्ञानिक व प्रामाणिक आंकड़ा मिलता रहेगा। देश के नगर व महानगर वार्डो में विभक्त हैं। अत: वार्डवार जनगणना के लिए गिनती की उपरोक्त प्रणाली ही अपनाई जाए। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।

सुलभ, पारदर्शी और समावेशी न्याय सबकी जरूरत

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई का यह कहना कि न्यायिक निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी को मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं लेना चाहिए अत्यंत विचारणीय तथ्य है, प्रौद्योगिकी मानव मस्तिष्क का स्थान भला कैसे ले सकती है जबकि उसकी भूमिका सहायक से अधिक नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति गवई लंदन विविद्यालय से संबद्ध स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस) में 'भारतीय कानूनी पण्राली में प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर आयोजित व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उनका यह कहना बिल्कुल उचित है कि स्वचालित वाद सूचियों, 'डिजिटल कियोस्क' और आभासी सहायकों जैसे नवाचारों का स्वागत किया जा सकता है। पर विवेक, सहानुभूति और न्यायिक व्याख्या बेशकीमती हैं।

प्रौद्योगिकी इनका स्थान कभी नहीं ले सकती। भारत के पास तकनीकी दक्षता, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक जनादेश है, जिससे समानता, सम्मान और न्याय के हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली पण्रालियां विकसित की जा सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करते ही न्यायमूर्ति गवई ने न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के अनुसंधान और योजना केंद्र के साथ चर्चा की शुरुआत की थी।

प्रधान न्यायाधीश की इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रहा जा सकता कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय विवेक का स्थान लेने के लिए न किया जाए। हालांकि कुछ मामलों में न्यायपालिका ने प्रौद्योगिकी को अपनाना शुरू किया है, लेकिन एआई के इस्तेमाल के मामले में केस प्रबंधन से लेकर कानूनी अनुसंधान, और दस्तावेज के अनुवाद तक भरपूर सावधानी जरूरी है। दुनिया भर में कानूनी पण्रालियों में एआई के नैतिक उपयोग पर गंभीर बहस चल रही है।

एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, गलत सूचना, आंकड़ों में हेरफेर और गोपनीयता जैसे मामलों ने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है। पीड़ित की पहचान उजागर होने का खतरा भी बना रहता है। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरे, एआई उपकरणों के उचित विनियमन और निगरानी के अभाव में वे मनगढ़ंत उद्धरण या पक्षपातपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। न्याय तक पहुंच केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। सुलभ, पारदर्शी और समावेशी न्याय सबकी जरूरत है।

सु-विचार

जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नही हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान..!

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाऐं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

निशुल्क योग शिविर में समनवित सामूहिक योग का प्रदर्शन

दुर्ग। जिला आयुष अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में नाना नानी, दादा दादी पार्क में योग संगम थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें डॉ. जया साहू के द्वारा योग गतिविधियों के बारे में बताया गया। डॉ. मनीन्द्रमोहन श्रीवास्तव के द्वारा हरित योग की जानकारी देकर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। डॉ. नम्रता यादव के द्वारा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण किया गया। आज का थीम योग संगम का यही उद्देश्य है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल पर अधारित एक समनवित सामूहिक योग प्रदर्शन सुनिश्चत करना है। इसी थीम के अंतर्गत भिलाई 03 के शिव पब्लिक स्कूल में योग चिकित्सक डॉ. अकांक्षा मिश्रा द्वारा अष्टांग योग पर व्याख्यान दिया एवं डॉ. सरला बांधे द्वारा जीवन शैली मे योग के महत्व को बताया गया। जिले के विभिन्न संस्थाओं में 17 से 21 जून तक निशुल्क योग शिविर जारी है जिसके अंतर्गत रोजाना हजारों लोग लाभांवित हो रहे है एवं जनसमुदाय को आहार विहार की जानकारी देते हुए अंकुरित चना, गुड़, सत्तु बांटा जा रहा है।

नरेंद्र बंजारे को मिला प्रभारी महापौर का दायित्व

दुर्ग। दुर्ग नगर पालिक निगम महापौर अलका बाघमार दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर इंदौर रवाना हो गई हैं। उनकी अनुपस्थिति में, प्रभारी वित्त विभाग के सदस्य नरेंद्र बंजारे को दो दिनों के लिए प्रभारी महापौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।महापौर श्रीमती बाघमार ने यह आदेश जारी करते हुए शहर के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह निर्णय लिया है। प्रभारी महापौर नरेंद्र बंजारे शुक्रवार सुबह से महापौर चेंबर में अपना दायित्व संभालेंगे। इस दौरान वे महापौर के विभागीय कार्यों और महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। शहर का कामकाज नहीं होगा प्रभावित प्रभारी महापौर बंजारे ने आश्वस्त किया है कि उनकी देखरेख में शहर का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहेगा और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य प्रभावित नहीं होगा। वे निकाय के प्रशासनिक कार्यों, जैसे कि सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली, आदि की देखरेख करेंगे और महत्वपूर्ण बैठकों व कार्यक्रमों में भी प्रतिनिधित्व करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसः खालसा पब्लिक स्कूल परिसर में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम

दुर्ग। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देश के परिपालन में जिले में 21 जून 2025 को 'योगा संगम' एवं 'हरित योग' थीम पर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया जाना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कार्यक्रम का आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल परिसर दुर्ग में प्रातः 7 से 7.45 बजे के मध्य किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित इस महत्वपूर्ण आयोजन में अधिक से अधिक विद्यालय/ कर्मचारी व समस्त स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है।

निदेशक एवं निदेशक प्रभारी-अतिरिक्त प्रभार मनीष राज गुप्ता ने संयंत्र में परियोजनाओं की समीक्षा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल के निदेशक एवं निदेशक प्रभारी अतिरिक्त प्रभार मनीष राज गुप्ता 19 जून 2025 को भिलाई के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे। प्रातः भिलाई निवास पहुंचने पर उनका स्वागत कार्यपालक निदेशक पवन कुमार एवं कार्यपालक निदेशक राकेश कुमार ने किया। श्री गुप्ता के साथ उनकी धर्मपत्नी कविता गुप्ता भी उपस्थित रही। भिलाई दौरे के क्रम में मनीष राज गुप्ता ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मरोदा-1 जलाशय स्थित 15 मेगावाट क्षमता वाले निर्माणाधीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट के परियोजना स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की स्थापना से जुड़े तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की और विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उनके साथ कार्यपालक निदेशक राकेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण राय भल्ला, मुख्य महाप्रबंधक राजीव पांडे, मुख्य महाप्रबंधक वी. वेंकटेशन, महाप्रबंधक आलोक सिंह सहित बीएसपी एवं एनएसपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान गुप्ता को इस परियोजना के तकनीकी विवरण जैसे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की डिज़ाइन, सोलर मॉड्यूल इंस्टॉलेशन तकनीक, केबलिंग सिस्टम, इन्वर्टर सेटअप एवं कंट्रोल रूम संचालन की स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट अपने अंतिम चरण में है, जिसका क्रियान्वयन एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है व यह परियोजना स्थापना के उन्नत चरण में है जिसके जुलाई 2025 तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है। एनएसपीसीएल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे प्रतिवर्ष लगभग 33 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 22,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने आगामी चरण में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके तहत मारोदा जलाशय में अतिरिक्त 20 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना तथा नंदनी एयरस्ट्रिप में 25 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी।

निदेशक तथा निदेशक प्रभारी - अतिरिक्त प्रभार (बीएसपी) के मनीष राज गुप्ता ने 15 मेगावाट निर्माणाधीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट के परियोजना स्थल के निरीक्षण के उपरांत दोपहर में भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के अन्य सदस्यों के साथ बैठकें कीं, जिनमें विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बीएसपी एम्पलाइज कोऑपरेटिव एंड वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-4 ने मई माह के रिटायर कर्मियों को दी विदाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी एम्पलाइज कोऑपरेटिव एंड वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-4 ने समारोह का आयोजन कर माह मई 2025 में भिलाई स्टील प्लांट की सेवा से निवृत्त हुए अपने सदस्य कर्मियों को ससम्मान विदाई दी। इस दौरान रिटायर कर्मियों ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए सोसाइटी से अपने लगाव को लेकर उद्गार व्यक्त किए। इनमें कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो अपने पिता के बाद स्वयं इस सोसाइटी के सदस्य बनें।

स्वागत उपरांत सोसाइटी के अध्यक्ष पूरनलाल देवांगन ने रिटायर कर्मियों को सम्मान पत्र, मिठाई, श्रीफल व अंतिम भुगतान का चेक प्रदान कर उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रिटायर हुए वरिष्ठ साथियों का सोसाइटी को आज इस मकाम पर लाने अहम योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। स्वागत व सम्मान के लिए आभार जताते हुए वरिष्ठ कर्मियों ने भी अपनी बातें रखीं। ऑक्सीजन प्लांट-2 के उत्तम कुमार ने बताया कि उनके सेवाकाल के शुरुआती दिनों में वरिष्ठों ने इस सोसाइटी को लेकर जो सलाह दी थी, वही सलाह हम बीएसपी ज्वाइन करने वाली नई पीढ़ी को भी देते रहे हैं कि कि सदस्य बनना है तो सेक्टर 4 सोसाइटी ही बेहतर है।

ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल से गुहाराम उइके ने कहा कि इस सोसाइटी से कभी कोई शिकायत नहीं रही और आगे भी किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी। प्लांट व्हीकल पूल से सुदर्शन लाल तामुरकर ने कहा कि सदस्य बनने 1995 में किन्हीं वजहों से रोक लगी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने इंतजार किया। हमने तय कर लिया था कि भले ही देर हो जाए लेकिन सदस्य तो सेक्टर 4 सोसाइटी का ही बनना है। अंततः कुछ समय बाद हमें अवसर मिला। स्टील मेल्टिंग शॉप-3 से आनंद कुमार वर्मा ने भावुक होकर बताया कि उन्हें उनके पिता ने इस सोसाइटी का सदस्य बनाया था और एक ही परिवार की दूसरी पीढ़ी के दौर पर उन्होंने सदस्यता ली थी।

स्टील मेल्टिंग शॉप-2 से इकरामुद्दीन ने कहा- मेरा जन्म सेक्टर-4 में हुआ और यहीं पढ़ लिख कर भिलाई स्टील प्लांट की सेवा के बाद अब सेक्टर-4 में इस आत्मीय समारोह में विदाई ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सोसायटी के लोन से हुई और सोसायटी के अंतिम भुगतान के रूप में एक लाख रुपये से भी ऊपर लेकर जा रहा हूं यह गर्व की बात है। मशीन असेंबलिंग एंड री-इंजीनियरिंग शॉप (मार्स) 1 से धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल और ब्लास्ट फर्नेस से कामता सिंह ने कहा सोसायटी के ऊपर हमेशा विश्वास रहा है, अब रिटायरमेंट के बाद भी हम सोसाइटी में नियमित सदस्य बने रहे इसकी व्यवस्था जरूर कीजिए।

रिटायर कर्मियों में स्टील मेल्टिंग शॉप-2 से भोजराम ठाकुर, ईश्वरी लाल खंडासु, हैवी मेंटेनेंस (ई) से देवेंद्र ट्रांसपोर्ट एंड डीजल ऑर्गेनाइजेशन से ई.श्यामसुंदर राव, सुरेंद्र कुमार ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, रिफ्रैक्टरीज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट-1 से वीएस मूर्ति, वाटर मैनेजमेंट से अदल राम, वायर रॉड मिल से प्रमोद कुमार और रिफ्रैक्टरीज मटेरियल प्लांट-3 से उत्तम कुमार नायक शामिल हैं।

जिस मार्ग पर स्वामी की प्रतिमा स्थापित, उस मार्ग का नामकरण 35 साल पहले हुआ - ललित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। जहां लोग कूड़ा कड़का फेंकते थे उस स्थान को संवारा जा रहा है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कृष्णा टॉकिज मार्ग से आशीष नगर जाने वाले मार्ग पर हुए सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण किया। विधायक ने स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की प्रतिमा आज स्थापित हो रहा है, लेकिन नागरिकों ने इस मार्ग का नाम 35 वर्ष पहले ही विवेकानंद मार्ग रख चुके है।

दुर्ग ग्रामीण विधायक ने कहा कि पार्षद मनीष यादव सौन्दर्यीकरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इसके पहले भी वे अपने वार्ड में आदिवासी समाज भवन जाने वाले मार्ग पर कलाकृति तैयार कर खुबसूरत बनाया है। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में दुर्ग सांसद प्रतिनिधि दीपक पप्पू चंद्राकर, मण्डल अध्यक्ष अनुपम साहू, पार्षद रमा साहू समेत बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक थे। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित नागरिकों से चर्चा की। जैसे ही विधायक की नजर 92 वर्षीय वृद्ध हनुमान सिंह पर पड़ी उन्होंने स्वयं हनुमान सिंह का हाथ पकड़ा और आतिथ्य का न्योता दिया। विधायक ललित ने प्रतिमा का अनावरण वरिष्ठ नागरिक से कराया।

बैंकों में लंबित शासकीय योजना आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें: कलेक्टर सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अग्रणी बैंक कार्यालय दुर्ग द्वारा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुआ। बैठक के प्रारंभ में बैंको की साख जमा अनुपात (सीडी रेसियो) पर चर्चा हुई। जिन बैंकों का साख जमा अनुपात कम हैं, उन बैंकों को अगले तिमाही बैठक तक सुधार करने को कहा गया।

कलेक्टर श्री सिंह ने दुर्ग जिले की सभी बैंकों में चल रहे सेवा योजनाओं की योजनावार समीक्षा की एवं बैंकों में लंबित आवेदनों को समयावधि में निराकृत कर लक्ष्य प्राप्त करने निर्देशित किया। जिला व्यापार उद्योग केन्द्र से प्राप्त बैंकों में लंबित आवेदनों की स्वीकृति करने एवं अस्वीकृति की जानकारी स्पष्ट रूप से उचित कारण दर्शाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश सभी बैंकों को दिए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत मत्स्यपालन एवं पशुपालन की समीक्षा करते हुए विभागों से बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। कलेक्टर ने संबंधित विभागों से इन लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुरक्षा योजना (पीएमजेजेबीवाय एवं पीएमएसबीवाय) के अंतर्गत बैंकों में लंबित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा योजना के दाता प्रकरणों पर कार्रवाई कर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे, भारतीय रिजर्व बैंक नवीन तिवारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रकाश राव, आरसेटी निदेशक दीपक कुमार पटेल अंशु गोयल जिला विकास अधिकारी नाबार्ड सहित मत्स्य पालन विभाग, कृषि विभाग, एनआरएलएम, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार उद्योग केंद्र के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक व एफएलसी, सीएफएल काउंसलर उपस्थित थे।

ट्रेनों में बिना इंटरनेट आधार की जांच कर सकेंगे टीटीई

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। ट्रेनों में अब फर्जी व एडिटेड आधार कार्ड ले जाना महंगा पड़ सकता है। ट्रेनों में बिना इंटरनेट के टीटीई आधार कार्ड की भी जांच सकेंगे। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि यात्री ने सही आधार कार्ड दिखाया है या उसने किसी विशेष योजना का लाभ लेने फर्जी व एडिटेड आधार प्रस्तुत किया है। इसके लिए टीटीई आधार जांच करने के लिए अलग से सुविधा दी जा रही है। इससे ट्रेनों से होने वाला फर्जीवाड़ा रूकेगा।

रेलवे ने अब तय किया है कि चलती ट्रेन में टीटी (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) आधार कार्ड की जांच भी कर सकेगा। रेलवे की ओर से टीटीई को एम-आधार मोबाइल ऐप का एक्सेस दिया जा रहा है, जिससे वे यात्री का आधार कार्ड स्कैन कर उसकी असली पहचान की जांच कर सकेंगे। यह ऐप यूआईडीएआई द्वारा बनाया गया है, जो बिना इंटरनेट के भी काम करता है। इस ऐप से आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यात्री का नाम, फोटो, जन्मतिथि और पता मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा। टीटी तुरंत पहचान सकता है कि आधार असली है या नहीं।

फर्जीवाड़ा करने वाले यात्री फसेंगे

फर्जीवाडा पकड़ाया तो बनेगा पुलिस केस

जांच में यदि आधार कार्ड फर्जी या एडिटेड निकला तो फर्जीवाड़ा करने वाले यात्री को तुरंत जीआरपी के हवाले किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। रेलवे ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार लोग दूसरे के आधार कार्ड या नकली पहचान पत्र दिखाकर ट्रेन में सफर करते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन के कोटे में लोवर बर्थ पाने के लिए उम्र को बढ़ाकर टिकट बनवाते हैं और आधार को एडिट कर प्रस्तुत कर देते हैं। अब नई तकनीक से इस तरह की गड़बड़ी पर लगाम लगेगी।

तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी किया है बड़ा बदलाव

रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार से लिंक अकाउंट और ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं, 15 जुलाई से हर तत्काल बुकिंग पर आधार से जुड़े मोबाइल पर मिला ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि टिकट बुकिंग के समय यूजर की पहचान पक्की की जा सके। रेल मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फर्जी एजेंट्स द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाना तथा इमरजेंसी में जरूरतमंद यात्रियों को समय पर टिकट उपलब्ध कराना है।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866
Premier sales: 8959493000
A Leela Electronics: 9425507772
Reena Electronics: 9329132299
Shree Electronics: 7000827361
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

व्यापारियों की जागरूकता के लिए साइबर एक्सपर्ट देंगे कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का डेलिगेशन चेंबर अध्यक्ष सतीश थोरानी के निर्देशानुसार एडिशनल एसपी क्राइम संदीप मित्तलजी से भेंट के बाद चर्चा कर आग्रह किया, साइबर क्राइम पुलिस एवं चैंबर के संयुक्त तत्वाधान में साइबर फ्रॉड विषय पर एक्सपर्ट टीम के द्वारा चेंबर भवन में व्यापारियों के हित में जल्द से जल्द कार्यशाला आयोजित की जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में चैंबर उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रकांत जैन, मंत्री राजेंद्र पारेख, राजीव जैन, निलेश साखला जितेंद्र लोढ़ा उपस्थित रहे।

राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाने के लिए सघन प्रयास करने के दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025-26 तक टी.बी. से मुक्त राज्य बनाने के लिए सघन प्रयास के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को राजभवन में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह-संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला को उक्ताशय के निर्देश देते हुए कहा कि टी बी के गंभीर मरीजों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करें। जो टी.बी. मरीज बीच में ही दवा का सेवन बंद कर देते है उन मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें दवा का पूर्ण कोर्स करने हेतु जागरूक किया जाए। टी.बी. मरीजों को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करें जिससे रोग के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। श्री डेका ने टी.बी. मरीजों को पर्याप्त पोषण आहार मिले इसके लिए अधिक से अधिक नि:क्षय मित्र बनाने के निर्देश भी दिए।बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा को 22 वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमलनारायण शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक भवन स्थित उनकी मूर्ति के समक्ष उन्हें नमन करते हुए महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सभी राजधानीवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड, संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमलनारायण शर्मा की सुपुत्री श्रीमती सविता पाठक, परिवार जनों, गणमान्य जनों, आम जनों ने बडी संख्या में पहुंचकर उन्हें 22वीं पुण्यतिथि पर नमन करते हुए मूर्ति स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

विधायक मिश्रा व महापौर चौबे ने मैकेनाइज्ड पार्किंग और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना का किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रायपुर नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत शहीद हेमूकालाणी वार्ड क्रमांक 28 के महालक्ष्मी मार्केट पंडरी में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, वित्त विभाग अध्यक्ष महेन्द्र खोडियार, शहीद हेमूकालाणी वार्ड पार्षद कृतिका जैन, जोन 3 अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉ. प्रमोद साहू, पंडरी कपडा बाजार व्यवसायी संघ अध्यक्ष सरल मोदी, मुख्य अभियंता यू.के. घलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, जोन 2 जोन कमिश्नर डॉ. आर.के. डोंगरे, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा सीनियर, पी.डी. घृतलहरे, आर्किटेक्ट जाकीर खान, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता विनोद देवांगन, सहायक अभियंता शैलेन्द्र पटेल, उप अभियंता अर्जिता दीवान, व्यापारीगणों, गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आमजनों की उपस्थिति में मैकेनाइज्ड पार्किंग और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना का भूमिपूजन श्रीफल फोडकर एवं कुदाल चलाकर करते हुए नागरिको को राजधानी शहर में एक और शानदार सौगात नगर निगम क्षेत्र में दी।

महालक्ष्मी कपडा मार्केट पंडरी में 24 कारो की पार्किंग हेतु संरचना का स्थापना कार्य 70 लाख रू. की स्वीकृत लागत से किया जायेगा। वहीं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट एनएनटी परियोजना के अंतर्गत महालक्ष्मी मार्केट पंडरी में 61 लाख रू. की स्वीकृत लागत से ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, एनएमटी हेतु पक्के क्षेत्र का निर्माण रोक मार्किंग व ट्रैफ्फिक साइनेज का कार्य किया जायेगा।

जानकारी दी गई कि महालक्ष्मी कपडा मार्केट पंडरी में मैकेनाइज्ड पार्किंग और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना के क्रियान्वयन से जहां भीड़ भाड़ में कमी आयेगी वहीं सड़क किनारे अवैध पार्किंग समाप्त होगी और यातायात सुगम और व्यवस्थित होगा। इससे सायकल और पैदल चलने वालो को प्रोत्साहन मिलेगा। बाजार क्षेत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकेगी और नागरिको की दुकानो तक बेहत्तर पहुंच हो सकेगी। सुरक्षा व्यवस्था सुधरेगी पैदल यात्रियो विशेषकर वरिष्ठ नागरिको, महिलाओं, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। संगठित संरचनाएं और सौंदर्ययुक्त विकास की दिशा में परियोजनाओ का कियान्वयन सार्थक पहल सिद्ध हो सकेगा। उक्त परियोजनाएं ना सिर्फ एक बाजार के क्षेत्र की भौतिक समस्याओ का समाधान करेंगी बल्कि राजधानी शहर रायपुर को स्मार्ट सुरक्षित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में अपना योगदान दे सकेंगी।

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा एवं महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने अधिकारियों को भूमिपूजन स्थल पर शीघ्र परियोजना कियान्वयन कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया एवं परियोजना का कियान्वयन जनहित में जनसुविधा विस्तार हेतु सतत मॉनिटरिंग कर गुणवत्तायुक्त तरीके से प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। शहीद हेमू कालाणी वार्ड पार्षद श्रीमती कृतिका जैन ने वार्ड क्षेत्र के तहत महालक्ष्मी मार्केट पंडरी में मैकेनाइज्ड पार्किंग एवं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना का कार्य भूमिपूजन कर प्रारंभ करवाने पर सभी वार्डवासियों की ओर से रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल को हार्दिक धन्यवाद दिया।

छत्तीसगढ़ में एक जुलाई से बढ़ सकती है जमीन की कीमत, दर का सर्वे हुआ पूर्ण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत जल्द ही बढ़ने वाली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 1 जुलाई से जमीन गाइड लाइन की नई दर लागू होने वाली है। इससे पहले पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की प्रचलित दर का सर्वे पूरा कर लिया है। फिलहाल मूल्य का विश्लेषण जिलेवार और क्षेत्रवार किया जा रहा है। इस काम में पिछले कुछ महीनों में हुई देर की वजह से नई गाइड लाइन जारी करने में विलंब हुआ है। खास बात ये है कि राज्य में आठ साल बाद नई दरें लागू होने जा रहीं हैं।

नई दरें आने से किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। दरअसल राज्य में सबसे अधिक जमीनें किसानों के पास ही है। किसी भी उपयोग के लिए सरकार द्वारा जो अभी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका मुआवजा मौजूदा गाइडलाइन दर पर होता है। जबकि किसानों की रोड से लगी जमीनों की असली कीमत गाइड लाइन से 10-10 गुना तक अधिक है। अब सरकार किसान की जमीन लेगी तो उसे भी नई दरों के हिसाब से मुआवजा देना होगा।

कच्चे का काम होगा बंद

जमीनों के सौदे के मामले में माना जाता है कि अधिकांश बड़ी टाउनशिप, कालोनियों के निर्माण के दौरान बिल्डर गाइडलाइन रेट के बजाय अपने हिसाब से जमीन की कीमत ग्राहक से वसूलते हैं और अंतर की राशि कच्चे में ली जाती है। यानी कम कीमत की जमीन का मूल्य अत्याधिक बढ़ाकर बिल्डर पैसा वसूलते हैं। अब नई दरें आने से इस काम में कमी होगी

मिलेगा अधिक राजस्व

नई दरें लागू होने से सरकार को पंजीयन से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होना तय है। अगर पूरे राज्य में औसत 20 प्रतिशत रेट बढ़ा तो सरकार के खजाने में जाहिर है अधिक राशि आएगी। क्योंकि तब रजिस्ट्री बढ़ी हुई दरों पर होगी। इसके साथ ही पंजीयन में काले धन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

पंजीयन विभाग के जानकार सूत्रों का कहना है कि नई गाइड लाइन दर आने के साथ ही पूरे राज्य में जमीन की कीमत कम से कम 10 प्रतिशत 15- या 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। कुछ खास इलाकों में यह दर 25 प्रतिशत तक भी अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जमीनों के मूल्य के सर्वे के दौरान अधिकारियों को मालूम हुआ है कि किस क्षेत्र में जमीन का प्रचलित मूल्य क्या है। इसी आधार पर नए रेट बनेंगे। रायपुर के 50 किलोमीटर के दायरे (रेडियस) में जमीन सबसे अधिक महंगी होने की संभावना है।

पंजीयन से मिले हैं 2900 करोड़ दूसरे राज्यों से बेहद कम

छत्तीसगढ़ को पंजीयन से पिछले वित्तीय वर्ष में 2900 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहां पंजीयन से सरकार को 40 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं। कर्नाटक में 30 हजार करोड़ रुपए और पड़ोसी मप्र की बात करें तो अकेले इंदौर शहर से 3 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं।

नगरीय नियोजन व भवन अनुज्ञा विभाग सलाहकार समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने ली बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर निगम नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग सलाहकार समिति की बैठक विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा की अध्यक्षता समिति सदस्य जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साह, पार्षद खगपति सोनी, कृष्णा सोनकर, सोहन लाल साहू रवि सोनकर, महेन्द्र औसर, विनय प्रताप सिंह ध्रुव, विनय पंकज निर्मलकर, शेख मुशीर, अपर आयुक्त पंकज के शर्मा, उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा, नगर निवेशक आभाष मिश्रा, जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं की उपस्थिति में हुई।

नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निवेश विभाग की टीम प्रत्येक दिन कम से कम 10 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सर्वे करे। नगर निगम नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग सलाहकार समिति की बैठक में नगर निवेश विभाग के अधिकारियों द्वारा समिति सदस्य पार्षदों को जानकारी दी गयी कि नगर निगम रायपुर के नगर निवेश विभाग द्वारा वर्ष 2019 से 25 फरवरी 2025 तक 329 अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही कर मुरूम रोड को सम्बंधित अवैध प्लाटिंग स्थल पर काटकर आवागमन बाधित किया गया है और अवैध प्लाटिंग का सूचना बोर्ड लगाया गया है। इसी प्रकार ऑनलाइन भवन अनुज्ञा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2025 तक 150 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों हेतु 6270 आवासीय प्रकरणों में 13 करोड़ 68 लाख 39184 रुपये और 961 व्यवसायिक प्रकरणों में 10 करोड़ 20 लाख 9007 रुपये कुल 23 करोड़ 88 लाख 48191 रुपये निगम कोष में जमा किये गए हैं।

रथयात्रा पर इस बार विशेष आयोजन जोहार जगन्नाथ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ में पहली बार एक अनूठे आध्यात्मिक आयोजन जोहार जगन्नाथ की शुरुआत होने जा रही है। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन आज कोतवाली चौक स्थित अनोपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स में किया गया। इस शुभ अवसर पर विधायक एवं जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पोस्टर का अनावरण किया और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

जोहार जगन्नाथ कार्यक्रम 94.3 मॉय एफएम और अनोपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को रथ यात्रा के आध्यात्मिक उल्लास से सीधे जोडना है। इस अभिनव प्रयास के अंतर्गत शुद्ध स्वर्ण एवं रजत के विशेष सिक्कों पर भगवान जगन्नाथ की पावन छवि उकेरी जाएगी, जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पुरी धाम स्थित भगवान जगन्नाथ को अर्पित की जाएंगी।

संकरी में शासन के सहयोग से अवैध कब्जा हटाओ अभियान हुआ शुरू, पंचायत व ग्रामीण सक्रिय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। विधानसभा आरंग व तहसील मंदिर हसौद के अधीन आने वाले ग्राम संकरी (जावा) में बुधवार से पंचायत ने शासन के सहयोग से एक बार फिर अवैध कब्जा हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। बीते दिनों पंचायत ने ग्रामीणों की सहमति से अवैध कब्जा हटवाने का प्रस्ताव पारित कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद पहुंचे राजस्व अमला द्वारा नाप-जोख कर अवैध कब्जों को चिन्हांकित करने के बाद पंचायत ने अवैध कब्जा हटवाना शुरू कर दिया है।

ज्ञातव्य हो कि अवैध कब्जों से बदरंग हो चले ग्राम संकरी में कुछ वर्षों पूर्व ग्रामीणों ने अवैध कब्जों को हटवा निस्तारी समस्या दूर की थी लेकिन कालांतर में ग्रामीण व्यवस्था के ढीला पड़ जाने से अवैध कब्जा की प्रवृत्ति फिर शुरू हो चली थी व बेजा कब्जाधारी निस्तारी भूमि पर कब्जा कर खेती करने लगे थे। एक दूसरे की देखादेखी रफ्तार से बेजा कब्जा बढने से आम निस्तारी की समस्या फिर आने लगी थी। ग्रामीणों व पंचायत की मनाही के बाद भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस पर ग्रामीणों की बैठक के बाद पंचायत ने अवैध कब्जा हटवाने का प्रस्ताव पारित कर बीते दिनों तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था।

जलभराव पर सख्त रुख: घरों में पानी घुसा तो जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

महापौर मीनल चौबे ने जोनों से जलभराव की मंगवाई जानकारी

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे एवं आयुक्त विश्वदीप ने निगम सीमा क्षेत्र में बारिश में आम जनता के घरों के भीतर जलभराव ना हो, यह यथासंभव सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय कर कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी है।

महापौर और आयुक्त ने चिन्हाकित जलभराव स्थलों की विशेष सफाई करवाकर मानसून के दौरान इन स्थलों पर विशेष सतर्कता और सजगता बनाये रखकर सतत मॉनिटरिंग जोन के स्तर पर करवाने निर्देशित किया है, ताकि जलभराव की समस्या जनअसुविधा का कारण ना बनने पाए। महापौर व आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि जोन के ऐसे क्षेत्र जहां जलभराव की समस्या होती है उसे चिन्हांकित कर हर हाल में आमजनों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने कहा गया है। जोन कमिश्नर जलभराव वाले क्षेत्रो का निरीक्षण करें एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराकर नागरिको को जलभराव की समस्या से निजात दिलाना सुनिश्चित करें। जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए मशीन, मानव बल, बोल्डर, पत्थर व अन्य संसाधन का उपयोग कर हर हाल में जलभराव को रोकने कहा गया है। जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके। सभी जोन क्षेत्रो में जलभराव वाले स्थान चिन्हांकित है वहां पूरा ध्यान रखे कि बरसात में पानी गिरने पर उस स्थान पर जल भराव ना होने पाये।

महापौर मीनल चौबे ने जोनों से जलभराव क्षेत्रों की जानकारी मंगवाई है. महापौर ने अत्यधिक बारिश के चलते जोन 1 के लक्ष्मी धरमकांटा ट्रांसपोर्ट, कोयला बस्ती, विजय नगर, गंगा नगर, बुनियाद नगर, न्यू आनंद नगर, रामेश्वर नगर, संजय गांधी नगर, शिव नगर, नहरपारा क्षेत्र, ब्रम्हदेयी पारा, सन्यासीपारा का निचला हिस्सा शहीद नगर, दीक्षा नगर, तुलसी नगर, सांई मंदिर के आगे, आदर्श नगर, बम्लेश्वरी नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या होती है इसे दूर करने निर्देशित किया है।

वहीं इसी क्रम में जोन 2 के घासपारा वाल्मिकी नगर, जयश्री राम नगर, दुर्गा नगर, झाझापारा, मांझीपारा, देवेन्द्र नगर सेक्टर 2.3, नर्मदापारा, पटरी लाईन, फाफाडीह कल्याण हास्पिटल, जागृति नगर न्यू कलिंग नगर, देवेन्द्रनगर थाना, खालसा स्कूल, आफिसर कालोनी, सरस्वती स्कूल गुजराती स्कूल, बीजेपी कार्यालय, जोन 3 के अनुपम नगर, शक्ति नगर, जगन्नाथ नगर, गांधी नगर, अनुव्रत रेसीडेंसी, आनंद नगर, कनाल रोड नाला, तीन मुंह नाला क्षेत्र, जोन 4 के नुरानी चौक गली नंबर 1, 2, 3 अरमान नाला, गणेश मंदिर के पास एवं पतंग गली, सत्ती बाजार गद्दा लाईन, गौरी शंकर मंदिर आकाशवाणी के पास, सथपती चौक, डॉ. सोलंकी गली, दयानंद नगर कटोरा तालाब क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने पर्याप्त संसाधन लगाने कहा गया है। जोन 5 के पंडित सखाराम दुबे स्कूल के पास, मिलेनियम चौक, पंकज गार्डन, प्रोफेसर कालोनी, डबरी पारा व जोन 5 अंतर्गत अन्य जलभराव क्षेत्र, जोन 6 के देवी लक्ष्मी हास्पिल के पीछे, विधायक विश्राम गृह, चौरसिया कालोनी, धरम नगर, आछी तालाब, परशुराम नगर व अन्य क्षेत्र, जोन 7 के डुमर तालाब, विप्र कालेज क्षेत्र, गोकूल नगर, गोपाल नगर, रामकुंड बस्ती, गीता नगर, राखी नगर सहित अन्य क्षेत्र, जोन 8 के अटल आवास आदर्श चौक, गोपाल पाण्डे ढांचा भवन, सत्यम विहार, सालासार ग्रीन्स के पास सरोना, चंदनडीह, जोन 9 के दया नगर, चंडीनगर, सांई नगर, जोन 10 के यहुआ चर्च के पास दया नगर, चडी नगर, सांई नगर क्षेत्र के रहवासियों को संभावित जलभराव की समस्या से राहत दिलाने संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर को संसाधन का उपयोग कर राहत दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मां बनने वाली हैं 31 साल की छोटी 'पू', साड़ी पहन किया बेबी बंप फ्लॉन्ट

'कभी खुशी कभी गम' की छोटी 'पू 'याद है? जिसे लोगों ने फिल्म में खूब पसंद किया, तो अब उनका किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मालविका राज मां बनने वाली हैं। हसीना ने अपनी गोदभराई की फोटोज शेयर करी। जिसमें वह साड़ी पहन बेहद सुंदर लगीं, तो उनके चेहरे पर ग्लो साफ नजर आया।

बॉलीवुड फिल्मों ने ऐसे कई किरदार दिए, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसमें 'कभी खुशी कभी गम' की 'पू' को कभी नहीं भूला जा सकता। करीना कपूर को 'पू' के किरदार में जितना प्यार मिला, उतना ही छोटी पू यानी कि मालविका राज को भी मिला। और, अब छोटी 'पू' 31 साल की उम्र में मम्मी बनने जा रही हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की, तो सब उनकी सादगी पर फिदा हो गए।

दरअसल, मालविका शादी के दो साल बाद जिंदगी के नए फेस में कदम रखने जा रही हैं। ऐसे में अब उनकी गोदभराई हुई। जिसके लिए वह साड़ी पहनकर तैयार हुई और स्टाइल के साथ ही अपने संस्कार दिखाकर दिल जीत गईं। ऐसे में वह बड़ी पू यानी करीना से कुछ कम नहीं लगीं और अब उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

मालविका ने अपनी गोद भराई की बेहद सुंदर- सी फोटोज शेयर की हैं। जिसमें वह पवन और प्रणव लेबल की खूबसूरत फ्लोरल साड़ी पहने नजर आ रही हैं। जिस पर बना रंग- बिरंगा पैटर्न कमाल का लगा और उसे स्टाइल करने का तरीका तो और भी दिल जीत गया। जहां होने वाली मम्मी के लुक की छोटी-छोटी डीटेल्स भी परफेक्ट लगीं।

फूलों के साथ सितारों से आई साड़ी में चमक

मालविका की साड़ी का कलर ग्रीन है, तो इसे रेड, येलो और पर्पल फ्लोरल पैटर्न से सजाया गया है। जिस पर लगे सेक्विन सितारे इसमें चमक लेकर आए, तो बॉर्डर ने इसे और निखार दिया। जिसे सुनहरे सितारों के साथ ही थ्रेड वर्क से बनाया और फूलों के बीच भी सेम यही तरीका अपनाया। लेकिन, लुक की हाइलाइट साड़ी का रफल पैटर्न और बॉर्डर पर लगी मोतियों वाली लटकन ने किया।

ब्लाउज की स्लीव्स हैं यूनिक

मालविका ने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना। जहां उन्होंने अपनी नेकलाइन को ब्रोड रखते हुए उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन बॉडर और स्लीव्स पर कलरफुल मोतियों की लटकन लगाई। जिन्हें मेगा स्लीव्स पर छोटा-बड़ा रखते हुए डिजाइन किया, जो ब्लाउज को यूनिक टच दे गया। वहीं, बैक पर भी डोरी लगाकर सेम मोतियों वाली लटकन लगाई गई। जिससे ब्लाउज के डिजाइन का आइडिया आप भी ले सकती हैं।

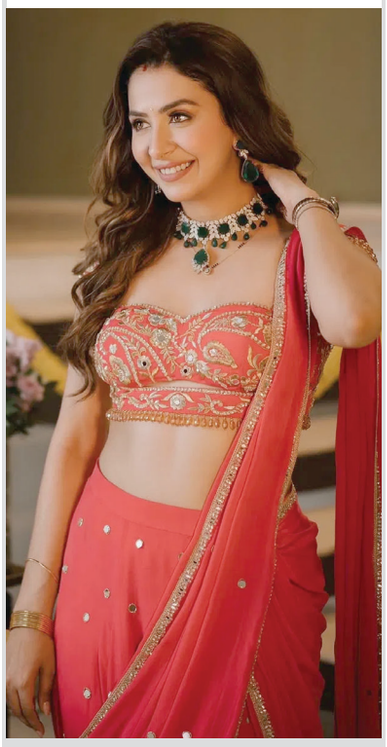

जान्हवी कपूर को 'उलझ' के ट्रेलर पर उनके कथित बॉयफ्रेंड एक्टर शिखर पहारिया ने की तारीफ कहा- 'माइंड ब्लोइंग'

जान्हवी कपूर ने 'उलझ' के ट्रेलर में सुहाना भाटिया के रूप में अपनी भूमिका से सभी को प्रभावित किया। उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्हें बधाई दी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुधांशु सरिया द्वारा निर्देशित, यह फिल्म उच्च-दांव वाली अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित एक मनोरंजक कहानी का वादा करती है। निर्माताओं ने मंगलवार को 'उलझ' का आकर्षक ट्रेलर जारी किया, जिसमें जान्हवी ने सुहाना भाटिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक युवा राजनयिक है जो साजिश और षड्यंत्र के जाल में उलझी हुई है।

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के ट्रेलर को फिर से साझा करते हुए शिखर ने लिखा, 'माइंड ब्लोइंग'। वाह वाह वाह मंदिर के दर्शन से लेकर पारिवारिक छुट्टियों तक, शिखर पहारिया को अक्सर जान्हवी के साथ देखा जाता है। हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य शादी में मधुर क्षणों के साथ इस जोड़े ने फिर से सुर्खियाँ बटोरीं। ट्रेलर में जान्हवी कपूर के किरदार सुहाना भाटिया को सबसे कम उम्र की डिप्टी हाई कमिश्नर के रूप में पेश किया गया है, जो एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है, जहाँ हर कदम पर कड़ी नजर रखी जाती है। उ

नका किरदार रूढ़ियों को चुनौती देता है, लंदन दूतावास में अपने करियर को परिभाषित करने वाले काम की जटिलताओं के बीच भाई-भतीजावाद के मुद्दे को सीधे तौर पर संबोधित करता है।सहकर्मी उसकी योग्यता पर संदेह करते हैं, उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं और उसे महज भाई-भतीजावाद मानते हैं, जिससे कथानक में तनाव की परतें जुड़ जाती हैं।

उलझ कब रिलीज होगी?

गुलशन देवैया रहस्यमयी अंडरकवर एजेंट के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं, जो कहानी में और भी रहस्य भर देते हैं। ट्रेलर रहस्यों और विश्वासघात की भूलभुलैया को छेड़ता है, एक आंतरिक लीक का संकेत देता है जो अंडरकवर एजेंटों के जीवन को खतरे में डालता है और सुहाना को जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष में डाल देता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक सुधांशु सरिया ने 'उलझन' की विषयगत गहराई पर जोर दिया, इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भीतर जटिल विकल्पों पर एक प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया, जिसे जान्हवी कपूर, गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू के आकर्षक प्रदर्शनों द्वारा बढ़ाया गया है।

प्रत्येक किरदार को ग्रे शेड्स के साथ चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को सस्पेंस और अप्रत्याशित खुलासे का रोलरकोस्टर देने का वादा करता है। आदिल हुसैन, राजेश तैलंग, मेयांग चांग, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी अभिनीत यह फिल्म अपनी जटिल कहानी और कूटनीतिक पेचीदगियों के प्रामाणिक चित्रण से दर्शकों को लुभाने का वादा करती है। सुधांशु सरिया और परवेज शेख द्वारा लिखित और अतिका चौहान द्वारा संवादों वाली 'उलझ' 2 अगस्त, 2024 को रिलीज होने वाली है।

60 साल की हो जाए मलाइका, ग्लैमर से देंगी सबको टक्कर

मलाइका अरोड़ा का नाम बॉलीवुड की उन हसीनाओं में शामिल है, जो बढ़ती उम्र के साथ और भी स्टाइलिश होती जा रही हैं। हसीना की जब भी नई तस्वीरें सामने आती हैं, वह अपने लुक्स से सबको लट्टू बना जाती हैं। जैसे कि अब उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से किया।

मलाइका अरोड़ा ग्लैमर और फिटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं। तभी तो वह चाहे देसी कपड़ों में नजर आए या फिर वेस्टर्न में, उनका स्टाइलिश अंदाज ही देखने को मिलता है। और, जब बात किसी फोटोशूट की आती है, तो वह अपनी किलर अदाओं से ही बाजी मार लेती हैं। ऐसे में अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरें लोगों को दीवाना बना रही हैं, जहां गोल्डन गर्ल बनकर वह बेहद कातिलाना लगीं।

दरअसल, मलाइका ने एचटी सिटी शो स्टॉपर के लिए फोटोशूट कराया। जहां उनका इतना ग्लैमरस रूप देखने को मिला कि लगा ही नहीं की वह 51 साल की हो चुकी हैं। गोल्डन गर्ल बनकर वह अपने हुस्न का जलवा बिखेर गईं और अब उनकी तस्वीरें हर जगह छाई हुई हैं। जिसकी फैंस भी तारीफ करते नहीं थक रहे।

वैसे तो मलाइका के सभी लुक्स एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन यहां शांतनु और निखिल के डिजाइनर गाउन में वह कहर ही ढा गईं। जहां उनका अंदाज और अदाएं भीगी जुल्फों में काफी हटके लगीं। तभी तो उनका ये लुक लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। जिसमें सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट करिश्मा पाटीदार ने मलाइका को स्टाइल किया।

ऐसा है गाउन

मलाइका के गाउन को स्ट्रैपलेस रखते हुए कॉरसेट स्टाइल बनाया गया है। जहां फैब्रिक में ही गोल्डन लाइनिंग पैटर्न बना है, तो स्ट्राइप्स वाला डिजाइन इसे शानदार लुक दे गया। जिसे उन्होंने कई एलिमेंट्स ऐड करके और भी स्टनिंग बना दिया और मलाइका का स्टाइलिश रूप देखते ही बना।

स्कर्ट से ऐड हुआ ड्रामा

अब डीटेल्स की बात करें, तो मलाइका की स्कर्ट को फ्रंट से प्लीटेड डिजाइन देते हुए स्टाइल किया और फिर साइड में 3डी स्कल्पचरल पैटर्न क्रिएट करके इसे वॉल्यूमेनस गाउन बना दिया। जिस पर हुआ लेस फ्लोरल वर्क कमाल का लगा। जिसे साइड से उठी स्कर्ट के डिजाइन के नीचे वाले हिस्से पर खूबसूरती से बनाया। जिससे लुक में ड्रामा ऐड हुआ और हर बार की तरह मलाइका ग्लैमर का तड़का लगा गईं।

कॉरसेट भी लगा कमाल

मलाइका का स्कर्ट पोर्शन कमाल का है, तो मैचिंग कॉरसेट भी कुछ कम नहीं। इस पर पट्टी वाले पैटर्न के बाद सेक्विन सितारों और गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई, जो इसे क्लासी टच दे रही है। वहीं, दोनों साइड्स पर बेल जैसा डिजाइन बना है, जो नीचे मैचिंग स्कल्पचर्ड स्कर्ट तक जा रहा है और सुंदर लगा।

ग्रीन फ्लोरल ड्रेस में मोनालिसा ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, शेयर की स्टनिंग तस्वीर

भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा इन दिनों दुबई वेकेशन का लुत्फ उठा रही हैं और वहां से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर कर रही हैं। हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत फोटो पोस्ट की है जिसमें वह ग्रीन फ्लोरल ड्रेस में नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर दुबई के एक लग्जरी मॉल की है जहां मोनालिसा बेहद रिफ्रेश और रिलैक्स्ड मूड में दिखाई दे रही हैं। फोटो में मोनालिसा ने डीप नेकलाइन वाली स्लीवलेस ग्रीन ड्रेस पहनी है, जिस पर येलो और ग्रीन फ्लोरल प्रिंट है। खुले बाल, न्यूड मेकअप, लाइट पिंक लिपस्टिक और स्टेटमेंट जूलरी उनके लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ पर ब्रैसलेट और उंगलियों में स्टाइलिश रिंग्स पहन रखी हैं। उनकी मुस्कुराहट और कैमरे की तरफ आत्मविश्वास से दिया गया पोज़ फैंस का दिल जीत रहा है।

फैंस कमेंट सेक्शन में दिल और फायर इमोजी के साथ उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। किसी ने उन्हें सुंदर दिवा कहा, तो किसी ने लिखा हमेशा की तरह शानदार । इस पोस्ट को अब तक 12 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।

मोनालिसा हमेशा से ही अपने फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहती हैं। चाहे वे ट्रेडिशनल आउटफिट्स हों या वेस्टर्न, हर लुक में वह अपना यूनिक चार्म लेकर आती हैं। दुबई वेकेशन की यह तस्वीरें एक बार फिर यह साबित करती हैं कि मोनालिसा न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि एक ट्रेंडसेटर फैशन आइकन भी हैं।

कब ऑन एयर होगा नया शो Pati Patni aur Panga मुनव्वअर फारुकी होंगे होस्ट

कलर्स टीवी एक बार फिर दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है कुछ हटके-एक ऐसा रियलिटी शो, जिसमें ग्लैमर, रोमांस, कॉमेडी और रिश्तों का असली टेस्ट देखने को मिलेगा. इस नए शो का नाम है 'पति, पत्नी और पंगा: जोड़ियों का रियलिटी चेक', जिसे होस्ट करेंगे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे। शो का फॉर्मेट ऐसा है जिसमें ग्लैमरस जोड़ियों को आम रिश्तों की तरह मुश्किल सवालों और टास्क से गुजरना होगा, और दर्शकों को मिलेगा एकदम रियल एंटरटेनमेंट।

ये जोड़ियां लेंगी रियलिटी टेस्ट में हिस्सा

शो में हिस्सा लेने जा रही हैं फिल्म और टीवी की कुछ सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियां। बताया जा रहा है कि इन 7 कपल्स को शामिल किया गया है। रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला, हिना खान और रॉकी जायसवाल, स्वरा भास्कर और फ्हाद अहमद, गीता फोगाट और पवन कुमार, गुरमीत चौधरी और देबिना बोनर्जी, सुदेश लेहरी और ममता लेहरी, अविका गोर और मिलिंद चंदवानी। हर कपल के रिश्ते में जहां प्यार है, वहीं चुनौतियां भी हैं और यही देखने को मिलेगा इस शो में, लाइव और बिना किसी फिल्टर के।

क्या होगा शो का कांसेप्ट?

'पति, पत्नी और पंगा' में हर एपिसोड एक नई चुनौती लेकर आएगा। इन चुनौतियों को पूरा करते हुए जोड़ियों को टीम वर्क, परस्पर

समझ और धैर्य का परिचय देना होगा। शो में दिखेगा. टास्क बेस्ड एंटरटेनमेंट, हल्के-फुल्के झगड़े और मजेदार तू-तू मैं-मैं। रियल रोमांटिक मोमेंट्स और ढेर सारी हंसी के पल इस शो का उद्देश्य ये दिखाना है कि कैमरे के पीछे इन सेलेब जोड़ियों की जिंदगी कितनी असली और जटिल है जैसी आम लोगों की होती है।

कब से होगा ऑन एयर?

यह शो कलर्स के पॉपुलर शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' की जगह प्रसारित किया जाएगा। शूटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका धमाकेदार प्रोमो टीवी और सोशल मीडिया पर आने वाला है। ऑन एयर डेट और टाइम स्लॉट की जानकारी चैनल द्वारा ऑफिशियली जल्द जारी की जाएगी।

लोगों को हैं टूथपेस्ट से जुड़े ये पांच आम भ्रम, जानिए इन सभी की सच्चाई

दांतों को स्वस्थ और सफेद बनने के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर कई भ्रम और गलतफहमियां प्रचिलित हैं। कई लोग मानते हैं कि केवल महंगे टूथपेस्ट ही कारगर होते हैं या ज्यादा मात्रा में इसे लगाने से ही फायदा होता है। हालांकि, इनमें से ज्यादातर बातें मिटक साबित होती हैं। आइए आज हम मिलकर टूथपेस्ट से जुड़े कुछ आम भ्रमों पर चर्चा करते हैं और उनकी सच्चाई जानते हैं।

महंगा टूथपेस्ट ही होता है बेहतर

कई लोग मानते हैं कि महंगा टूथपेस्ट हमेशा बेहतर होता है और यह दांतों को ज्यादा सफेद बनाता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि महंगे ब्रांड हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते। कई बार सस्ते ब्रांड भी अच्छे परिणाम देते हैं। इसलिए कीमत देखकर ही चयन नहीं करना चाहिए। गुणवत्ता और असर को ध्यान में रखते हुए ही टूथपेस्ट चुनना चाहिए। इससे आपको सही जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सा टूथपेस्ट आपके लिए बेहतर है।

बच्चों के लिए होता है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट

फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट को लेकर भी कई भ्रम फैले हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लोराइड केवल बच्चों के लिए जरूरी होता है और बड़ों को इसकी जरूरत नहीं होती। सच्चाई यह है कि फ्लोराइड दांतों की सुरक्षा के लिए अहम होता है, चाहे उम्र कोई भी हो। यह दांतों को कीड़ों से बचाने में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसलिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट का उपयोग करना फायदेमंद होता है।

सफेद फोम वाला टूथपेस्ट होता है ज्यादा असरदार

बहुत से लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा फोम, उतने सफेद दांत। हालांकि, असलियत में फोम सिर्फ सफाई करने में मदद करता है और सफेदी से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए फोम देखकर ही टूथपेस्ट का चयन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसकी गुणवत्ता और असर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप चमकदार दांत पा सकें। इससे आप सही तरीके से अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं।

टूथपेस्ट का रंग होता है अहम

कई लोग सोचते हैं कि गहरे रंग वाले टूथपेस्ट ज्यादा असरदार होते हैं, जबकि असलियत में रंग का सफेदी से कोई संबंध नहीं होता। सफेद या नीले रंग का टूथपेस्ट भी उतना ही अच्छा काम करता है, जितना कि गहरे रंग वाला। इसलिए रंग देखकर ही चयन करना सही निर्णय नहीं होता है। इसके बजाय टूथपेस्ट गुणवत्ता और असर पर ध्यान देना चाहिए और खुद इस्तेमाल करके जांच भी करनी चाहिए।

ज्यादा क्रीम वाला टूथपेस्ट ही होता है अच्छा

यह भी एक आम धारणा है कि ज्यादा क्रीम वाला टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। ज्यादा क्रीम वाला टूथपेस्ट कभी-कभी दांतों की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ज्यादा क्रीम वाला टूथपेस्ट चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन भ्रमों को समझकर हम अपने दांतों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

स्वस्थ रहने के लिए वजन कम करना जरूरी नहीं, हार्वर्ड के अध्ययन में हुआ खुलासा

लोगों की यह मानसिकता है कि स्वस्थ रहने के लिए वजन घटाना जरूरी होता है। एक अध्ययन इस बात को गलत साबित करता है। इस अध्ययन के जरिए सामने आया है डाइटिंग करने वाले लोगों का वजन कम न भी हो तब भी उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। यह अध्ययन कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए वजन घटाना आवश्यक नहीं होता है।

इजरायल के विश्वविद्यालय ने भी दिया अध्ययन में योगदान

इस अध्ययन को हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और इजरायल के बेन गुरियन विश्वविद्यालय ने मिलकर पूरा किया है। इसके माध्यम से पता चला है कि स्वस्थ डाइट का पालन करने वाले लगभग एक तिहाई लोगों का वजन कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में प्रभावशाली सुधार देखा गया। हाल ही में इस अध्ययन को यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया था।

761 लोग बने इस अध्ययन का हिस्सा

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने इजरायल में रहने वाले 761 लोगों पर नजर रखी, जिनका वजन ज्यादा था। इन सभी को तीन बड़े

पैमाने वाले कार्यस्थल-आधारित पोषण परीक्षणों में शामिल किया गया, जो प्रत्यक्ष, केंद्रीय और प्रत्यक्ष प्लस थे। सभी प्रतिभागियों को एक सख्त डाइट का पालन करने को कहा गया था। सभी ने 18 से 24 महीनों तक अलग-अलग प्रकार की पौष्टिक डाइट का पालन किया और शोधकर्ताओं ने उनके वजन का आकलन किया।

क्या रहे इस अध्ययन के नतीजे?

शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से लो-कार्ब, लो-फैट, मेडिटरेनियन और ग्रीन मेडिटरेनियन डाइट अपनाने के लिए कहा था। शोध से सामने आया कि 36 प्रतिशत प्रतिभागियों ने करीब 5 प्रतिशत वजन कम कर लिया था। वहीं, 28 प्रतिशत लोगों का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था या फिर पहले से थोड़ा बढ़ गया था। इसके बाद शोधकर्ताओं को समझ आया कि वजन घटाने का स्वस्थ रहने से कोई सीधा संबंध था ही नहीं।

वजन घटाने पर ऐसे बदला प्रतिभागियों का स्वास्थ्य

अध्ययन के मुताबिक, वजन कम करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे थे। प्रत्येक किलोग्राम वजन कम होने से कोलेस्ट्रॉल में 1.44 प्रतिशत की वृद्धि, ट्राइग्लिसराइड्स में 1.37 प्रतिशत की कमी, इंसुलिन में 2.46 प्रतिशत की गिरावट, लेप्टिन में 2.79 प्रतिशत की कमी और यकृत वसा में 0.49 इकाई की गिरावट दर्ज की गई थी। इससे पता चला कि लोगों की शारीरिक जरूरतें अलग होती हैं, जिस कारण वजन घटाने पर उनका शरीर अलग-अलग प्रतिक्रिया देता है।

अध्ययन के एक लेखक ने कही यह बात

हार्वर्ड चैन स्कूल में महामारी विज्ञान विभाग में पोस्टडॉक्टरल रिसर्च प्रमुख और अध्ययन की लेखक अनात यास्कोल्का मीर ने कहा, हमें वजन घटाने को स्वास्थ्य के बराबर मानने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अपना वजन कम नहीं करते हैं, वे अपने चयापचय में सुधार कर सकते हैं और बीमारियों के दीर्घकालिक जोखिम को कम कर सकते हैं। यह आशा का संदेश है, असफलता का नहीं।

युक्तिकरण नीति से सुधर रही शिक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्कूलों में लौटी रौनक, हर विद्यालय में शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू युक्तिकरण नीति अब सार्थक परिणाम दे रही है। जिलेभर के स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था सुदृढ़ होने से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि छात्रों की उपस्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक के भरोसे संचालित स्कूलों में अब नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। इससे दूरस्थ अंचलों के बच्चों को अब विषयानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है।

बलरामपुर जिले में 311 एकल शिक्षक वाले और 14 शिक्षकविहीन विद्यालयों में युक्तिकरण के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई डेटा आधारित कार्ययोजना और संतुलित पुनर्विन्यास के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक का पद लंबी अवधि तक रिक्त न रहे।

बलरामपुर विकासखंड का प्राथमिक शाला महाराजगंज, जो लंबे समय से शिक्षकविहीन था, वहां युक्तिकरण नीति के तहत शिक्षक की पदस्थापना के बाद पुनः नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसी तरह प्राथमिक शालाएं लुर्गी, भीतर सौनी और मक्याठी जैसे एकल शिक्षक विद्यालयों में भी अब विषयवार शिक्षकों की तैनाती संभव हो पाई है।

युक्तिकरण नीति ने शिक्षकों का कार्यभार संतुलित किया है और विद्यार्थियों को समुचित विषयों की पढ़ाई मिल रही है। इससे विद्यार्थियों को न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, बल्कि जीवन कौशल और सर्वांगीण विकास की दिशा में भी वे आगे बढ़ पाएंगे।

विद्यालयों में दिखने लगा बदलाव

युक्तिकरण नीति का असर केवल शिक्षकों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण, बालसभा, पठन-संवर्धन, कला-संस्कृति गतिविधियों, अभिभावकों की संतुष्टि और समुदाय के विश्वास के रूप में भी देखने को मिल रहा है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाई दे रही है, बल्कि स्कूल और समाज के बीच साझेदारी को भी मज़बूत कर रही है। आने वाले समय में यह पहल छात्रों की उपस्थिति, वार्षिक परीक्षा परिणाम और समग्र शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

पुरी यात्रा के लिए मिली नई स्पेशल ट्रेन, 5 फेरों के लिए गोंदिया से खुरदा रोड तक चलेगी रथयात्रा स्पेशल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पुरी जाकर महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा देखने की इच्छा रखने वालों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। गोंदिया से खुरदा रोड तक पांच फेरों के लिए रथयात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गोंदिया ङ्क खुरदा रोड- गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल की सुविधा 26 जून से 07 जुलाई तक दी जा रही है । रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 08893 गोंदिया खुरदा रोड रथ यात्रा स्पेशल 26, 28, 30 जून एवं 02 और 5 जुलाई को गोंदिया से 13:30 बजे रवाना होकर 14:30 बजे डोंगरगढ़, 15:00 बजे राजनंदगांव, 15.58 बजे दुर्ग, 17.05 बजे रायपुर, 18:55 बजे मंदिर हसौद होते हुए अगले दिन सुबह 08.45 बजे खुरदा रोड पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08894 खुरदा रोड गोंदिया रथ यात्रा स्पेशल खुर्दा से दिनांक 28, 29 जून एवं 1,3,7 जुलाई को खुरदा रोड से 11:00 बजे रवाना होकर मंदिर हसौद 22:30 बजे, रायपुर अगले दिन 1:00 बजे, दुर्ग 1.58 बजे, राजनांदगांव 02.23 बजे, डोंगरगढ़ 02.48 बजे, गोंदिया सुबह 4:15 पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन: इस ट्रेन के कामर्शियल स्टापेज गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनंदगांव रायपुर, मंदिर हसौद, महासमुंद, बागबहरा, खरीयार रोड, नवापारा रोड, हरीशंकर रोड, कांटाभंजी, टीटलागढ़, बढ़मल, बलांगीर, लुईसिंगा, डूंगरीपाली, बरपाली, बरगढ़ रोड, संबलपुर, रेराखोल, बोविंडा।

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत प्राथमिक शाला गोगांव को मिले 7 नए शिक्षक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।

इसी क्रम में रायपुर जिले की शासकीय प्राथमिक शाला गोगांव में 7 नए शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। पहले की तुलना में अब इस विद्यालय में कुल 17 शिक्षक हो गए हैं, जिससे 421 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। अब छात्र-शिक्षक अनुपात बेहतर हो गया है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल पा रही है। युक्तियुक्तकरण के तहत जिले के अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार विभिन्न विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

शाला के प्रभारी जीवराखन साहू ने बताया कि युक्तियुक्तकरण से पूर्व यहां 10 शिक्षक थे तथा विद्यार्थियों की संख्या 488 थी। सभी बच्चों को समुचित रूप से ध्यान देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब युक्तियुक्तकरण के बाद 17 शिक्षक हो गए हैं।

अब 30 से 35 बच्चों का एक बैच बनाकर विद्यार्थियों को अधिक समय तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं। पालकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इस पहल पर प्रसन्नता जताई है। अब बच्चे पहले से अधिक उत्साह के साथ स्कूल आ रहे हैं और पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं।

जल संरक्षण की अनूठी पहल : कबीरधाम जिले में घर-घर बना सोख पिट, नागरिक कर रहे है श्रमदान

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। कबीरधाम जिले में वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में मोर गांव - मोर पानी अभियान के तहत 20 जून 2025 को एक व्यापक जल संरक्षण महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज जिले के चारों विकासखण्ड कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा के जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक ली।

बैठक में सरपंच, उप सरपंच, सचिव, पंच, रोजगार सहायक, सक्रिय महिला, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक मित्र, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग व कृषि विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी, महिला स्व-सहायता समूहों की अध्यक्ष और सचिव से ग्राम स्तर की तैयारियों की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिले में गिरते भूजल स्तर को संजीवनी देने और वर्षा जल के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कबीरधाम जिले में मोर गांव - मोर पानी अभियान के अंतर्गत 20 जून 2025 शुक्रवार को जल संरक्षण महाअभियान चलाया जाएगा। इस विशेष दिन पर जिले के सभी नागरिक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रमदान कर अपने-अपने घरों में सोख पिट (सोखता गड्ढा) का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जमीनी स्तर के अधिकारी इसके लिए पूरी तैयारी कर ले।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में लोगों से संपर्क कर इसके लिए जागरूक करे। गांव में आज ही इसके लिए मुनादी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में की सोच को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। यह सभी के जन सहयोग से ही संभव हो सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि इस अभियान में हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। बरसात का पानी यदि घर के भीतर सोख पिट (सोखता गड्ढा) के माध्यम से जमीन में समा जाए, तो भूजल स्तर में सुधार संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक अभियान की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतें गांववार लक्ष्य तय कर सुनिश्चित करें कि हर घर में सोख पिट का निर्माण किया जाए। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, जिससे न केवल जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जल स्रोत भी उपलब्ध हो सकेगा।

बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि जल संरक्षण महाअभियान का मुख्य उद्देश्य कबीरधाम जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर की गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल करना है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में मोर गांव - मोर पानी अभियान के अंतर्गत सभी घरों में सोख पिट का निर्माण कर वर्षा जल को घर-घर में संरक्षित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल के माध्यम से घर का पानी घर में और गांव का पानी गांव में की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जाएगा। अभियान के दौरान लोगों को जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए एक साथ एक ही समय पर शपथ दिलाकर जनसहभागिता को प्रेरित किया जाएगा।

अभियान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कबीरधाम जिले के चारों विकासखंडों कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा को ग्राउंड वॉटर बोर्ड द्वारा दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कवर्धा एवं पंडरिया को क्रिटिकल ज़ोन तथा बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा को सेमी-क्रिटिकल ज़ोन में रखा गया है।

डंपसाइट सुधार के लिए राजकोट का सतत मॉडल

16 लाख टन कचरे से भरे एक दशक पुराने डंपसाइट को 20 एकड़ के हरे-भरे शहरी वन में बदल दिया

नई दिल्ली (पीआईबी)। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की शुरुआत के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसमें लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के लक्ष्य पर जोर दिया गया। एसबीएम-यू 2.0 ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर और आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में लक्ष्य जीरो डंपसाइट पहल की शुरुआत करके इस दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। इसे देखकर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के कई शहरों ने अपशिष्ट स्थलों को सुधारने का काम शुरू किया है।

राजकोट इस परिवर्तनकारी पहल का एक उदाहरण है। शहर में प्रतिदिन लगभग 700 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसका निपटान नकरावाड़ी डंपिंग साइट पर किया जाता था। समय के साथ, इस साइट पर लगभग 16 लाख टन कचरा जमा हो गया था। जवाब में राजकोट नगर निगम ने साइट को सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसका उद्देश्य न केवल कचरे को खत्म करना था, बल्कि क्षेत्र को एक स्वच्छ, हरे शहरी वन में बदलना भी था, जिसके परिणामस्वरूप 20 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण हुआ।

नकरवाड़ी साइट के कचरे का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद उन्नत मशीनों का उपयोग करके प्रसंस्करण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कचरा-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ), अर्ध-खाद और निष्क्रिय सामग्री को अलग किया गया। आरडीएफ को जामनगर में अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र में ले जाया गया, निष्क्रिय सामग्रियों को एक सुरक्षित लैंडफिल सुविधा (एलएलएफ) में भेजा और वृक्षारोपण के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। नकरावाड़ी साइट पर कचरे के सुधार में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 16 लाख टन से अधिक मिश्रित और सघन कचरे का प्रबंधन करना पृथक्करण और प्रसंस्करण को कठिन बनाता है, जबकि साइट के भारी प्रदूषण के लिए व्यापक भूमि तैयारी और मिट्टी संवर्धन की आवश्यकता होती है। श्रमिक और आस-पास के निवासी दुर्गंध और वायु प्रदूषण से प्रभावित थे, जिससे स्वास्थ्य खतरा पैदा हो रहा था। मानसून की बारिश ने संचालन को बाधित किया, और वृक्षारोपण के लिए उपचारित पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता के लिए 12 किमी पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता थी।

यह परियोजना खराब हो चुके डंपसाइट को उन्नत जैव विविधता के साथ एक संपन्न पर्यावरण-अनुकूल शहरी स्थान में बदलकर एक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, जो कचरे की चुनौती का समाधान करते हुए स्थिरता को बढ़ावा देती है। 30 एकड़ के हरित परिवर्तन पहल के लाभ के लिए कचरे को उपयोगी सामग्री और मूल्यवान संसाधनों में संसाधित किया गया। इस परियोजना ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव प्रदर्शित किए हैं। यह कचरे को उपयोगी उत्पादों में रिसाइकिल करके संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता कम हो जाती है और संसाधनों की कमी पर अंकुश लगता है। पृथक्करण, पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोजन जैसी प्रभावी अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियों के माध्यम से, यह पहल लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करती है, जिससे एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। यह 12 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए गौरीदाद एसटीपी से द्वितीयक उपचारित पानी का उपयोग करके जल संरक्षण में भी योगदान देता है, जिससे मीठे पानी के संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और शहरी वन में पानी का सतत उपयोग संभव होता है।

वैकल्पिक वित्तपोषण: एमएसएमई के लिए नई राह

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पारंपरिक बैंकिंग साधनों से आगे बढ़कर वैकल्पिक स्त्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के उद्देष्य से ''वैकल्पिक वित्तपोषण पर कार्यषाला'' का आयोजन किया गया।

जिला स्तरीय यह कार्यषाला भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की रेजिंग एण्ड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा के द्वारा आयोजित की गई। आरएएमपीयोजना भारत सरकार और विष्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित है, जिसका उद्देष्य एमएसएमई क्षेत्र का पुनरूत्थान और सषक्तिकरण किया जाना है।

यह कार्यशाला बुधवार 18 जून को कोरबा में आयोजित की गई, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों को एसएमई एक्सचेंज के माध्यम से वैकल्पिक वित्तपोषण के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यषाला का आयोजन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी दी गई, जो लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप को पूंजी जुटाने का एक विषेष मंच उपलब्ध कराती है।

कार्यशाला के षुरूआत में क्लाइंट फस्ट वेल्थ मैनेजमेंट के संस्थापक एवं प्रबंध निदेषक कुंजन गुप्ता द्वारा एमएसएमई अंतर्गत वेल्थ मैनेजमेंट और वित्तीय नियोजन के विविध पहलुओं से अवगत कराया गया। इसके पश्चात् एनएसई कोलकाता के मुख्य प्रबंधक श्री अविक गुप्ता द्वारा एनएसई इमर्ज में सूचीकरण की प्रक्रिया, पूंजी बाजार के नये अवसरों और लाभों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

सीएसआईडीसी रायपुर के प्रवीण द्वारा आरएएमपी योजना के अंतर्गत एमएसएमई सुविधा एवं वित्तीय बाजार तक बेहतर पहुंच की जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यषाला की अध्यक्षता जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा के द्वारा किया गया।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

सुपेला थानाक्षेत्र से लापता हुए तीन छात्र सुरक्षित घर लौटे

दुर्ग। सुपेला थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर, मिनीमाता चौक क्षेत्र से लापता तीन नाबालिग छात्र सकुशल अपने घर लौट आए हैं। तीनों छात्र परिजनों को बिना बताए नागपुर चले गए थे। तीनों के लौटने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि कृष्णा नगर, मिनीमाता चौक क्षेत्र के रहने वाले तीनों बच्चे 16 जून की शाम लगभग 4:30 बजे बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गए थे। इनमें से एक 16 वर्षीय छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ता है, दूसरा 15 वर्षीय उसका पड़ोसी है और तीसरा 7वीं कक्षा का छात्र है। बच्चों के गायब होने के बाद परिजनों ने अपने सभी परिचितों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने सुपेला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू की लेकिन 72 घंटों तक बच्चों का कोई सुराग नही मिला। बच्चों के लापता होने के बाद परिजनों से पूछताछ कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए थे। चूंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब उनके सकुशल लौट आने से पुलिस और परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

अवैध शराब बेचने वाला कोचिया पकड़ाया

बलौदा। बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले एक शराब कोचिया को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 9800 कीमत मूल्य का 98 पाव देशी मसाला शराब जप्त किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में आमजनों की शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में व्हाट्सएप अथवा कॉल के जरिए प्रदान की जा सकती है। समाधान सेल के माध्यम से आपराधिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ में भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 19.06.2025 को समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सिटी कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा भैंसाटसरा बलौदाबाजार में घेराबंदी कर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 01 आरोपी सूर्या देवार उम्र 19 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार को गिरफ्तार किया गया है।

शराब बेचते महिला गिरफ्तार

बिलासपुर। जिले की सरकण्डा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रही महिला को गिरफ्तार किया है तथा उसकेस पास से 75 पाव देशी प्लेन शराब जब्त किया है। मामले में आरोपी महिला के खिलाफ धारा - 34(2), आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज यिका है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुररजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

माइन्स में हाइवा वाहन लगाने के नाम पर ट्रांसपोर्टर से लाखों की ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर दिया धोखा, आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर को दो शातिरों ने लाखों का चूना लगा दिया। दरअसल ट्रांसपोर्टर को दोनों ने झांसा दिया कि उनकी हाइवा गाड़ियों को कोरबा कुसमुंडा खदान में लगवा देंगे। इसके बदले हर माह लाखों रुपए किराए के रूप में मिलेगा। ट्रांसपोर्टर उनके झांसे में आ गया और अपने 6 हाइवा वाहन इन्हें किराए पर दे दिए। इसके बाद न तो इनका किराया मिला और न ही किसी और प्रकार का लाभ। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मोरिद वार्ड 39, भिलाई-3 चरोदा निवासी शोभाराम साहू विठ्ठलपुरम से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। कुछ दिन पहले इनके दफ्तर में लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे पहुंचे और संपर्क बनाने के बाद दोनों ने बताया कि वे एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। दोनों ने अपनी कंपनी का नाम रूलबर्ड वाईट साफ्टेक प्रायवेट लिमिटेड बताया। दोनों ने बताया कि वे अन्य कंपनियो से मासिक भाड़े में वाहन लगाते हैं। दोनों ने शोभाराम को विश्वास दिलाया कि कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापर, रायगढ़ के कंपनी एवं कोल खदान के अधिकारियों के साथ सभी विधायक एवं मंत्रियों से उनके अच्छे संबंध हैं।

इसके बाद दोनों ने एक व्यक्ति को शोभाराम से मिलाया और बताया कि यह कोल कंपनी का मार्केटिंग अधिकारी है। उनकी बातो में आकर शोभाराम ने अपनी 6 हाइवा गाड़ी उन्हें दे दिया। दोनों ने बताया कि उनकी सभी गाडियों को कोरबा के कुसमुंडा माइन्स में लगा दिया गया है। यही नहीं एक फर्जी विडियो बनाकर भेजा गया जिसमें उनकी गाडियां दिख रही थी। इसके बाद एक व्यक्ति को माइंस का जीएम बताकर बात करवाया। उन्होंने कहा कि प्रति गाड़ी मासिक किया 2,40,000 रुपए रहेगा। इस प्रकार से मेरा एक माह का किराया 14 लाख 40000 रुपए बनता है।

जनवरी में आकर ले गए गाड़ियां

लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे 10 जनवरी 2025 को भिलाई-3 से शोभाराम की गाड़ी ले गए। उनके द्वारा कहा गया कि गाड़ी का ड्राईवर हमारा रहेगा तथा उनका पेमेंट भी वही लोग देगें। शोभाराम ने उनको CG07 CL 9025, CG07 CN 9027, CG07 CN 9029, CG07 CR 9031, CG07 CR 9032, CG07 CG 8891 नंगर की गाड़ियां दी। यह सभी गाड़ियां शोभा ट्रांसपोट के नाम से भिलाई-दुर्ग में चल रहा थी। गाड़ी देने के एक माह बाद जब शोभाराम ने किराए के लिए दोनों से संपर्क किया तो दोनों न नुकर करने लगे। शोभाराम को अब तक अपनी गाड़ियों का किराया नहीं मिला। जब कुसमुंडा खदान से जानकारी ली तो पता चला दोनों ने एडवांस रकम ले ली और और गाड़ी भी निकाल कर ले गए हैं। फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहे थे।

शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर

शोभाराम को यकीन हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में शिकायत के बा पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 318(4), 316(2) बीएनएस अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की। पूरे प्रकरण में कूट रचना, छलकपट से रकम ऐंठने वाले लोकेश नेताम (30) निवासी सेक्टर-8 सड़क नम्बर 41 मकान नंबर 1, तथा स्वपनिल शिंदे (31) निवासी आनंद बिहार फेस 2 डी/106 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक बंटी सिंह, आरक्षक राजकुमार सिंह की उल्लेखनिय भूमिका रही है।

मुंगेली पुलिस अधीक्षक का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण उत्कृष्ट कार्य पर जवानों को मिला नगद इनाम

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुंगेली। जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुंगेली के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने 18 जून की देर रात 1 बजे से 4 बजे तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भ्रमण करते हुए गश्त प्वाइंट, थानों एवं चौकियों की व्यवस्था को परखा।

पुलिस अधीक्षक ने अपने निरीक्षण के दौरान मुंगेली शहर के प्रमुख स्थानों जैसे दाउपारा चौक, पड़ाव चौक, नंदी

चौक, गोलबाजार चौक, बड़ा बाजार सहित थाना जरहागांव, लालपुर और लोरमी के गश्त प्वाइंटों का दौरा किया। इस दौरान वे अचानक संबंधित थानों में पहुंचे और रात्रिकालीन गश्त पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की।

थाना जरहागांव में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नंद लाल पैकरा, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण यादव, थाना लालपुर में उप निरीक्षक अमित गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र कुर्रे और थाना लोरमी में उप निरीक्षक सुन्दर लाल गोरले एवं आरक्षक सुनील भास्कर रात्रि गश्त करते मिले। ड्यूटी पर तत्परता से उपस्थित पाए जाने और संतोषजनक जवाब मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने इन सभी को नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया।

वहीं, ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए गए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) जारी किया गया है।

निरीक्षण के दौरान एसपी श्री पटेल ने देर रात बिना कारण घूमते पाए गए कुछ संदिग्धों से पूछताछ की और उन्हें अनावश्यक रूप से रात में न घूमने की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित गश्त, पेट्रोलिंग जारी रखें और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखें। साथ ही, रात में संदेहास्पद रूप से घूमने वालों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई से जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता और जवाबदेही स्पष्ट रूप से सामने आई है।

यातायात पुलिस ने दो दिन में की 193 गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पिछले दो दिनों में 193 गाड़ियों पर चालानी चालानी कार्यवाही की है।

कोरबा जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पिछले दो दिन में और 193 गाड़ियों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 55/177 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। अब तक इस अभियान के तहत कुल 256 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 76,800 का समन शुल्क वसूला गया है। अभियान के दौरान वाहनों के इंजन नंबर, चेचिस नंबर तथा वैध दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही चालानी कार्रवाई की गई।

कोरबा पुलिस की नागरिकों से अपील की है कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ऐसे वाहन अपराधियों को छुपने और अपराध को अंजाम देने में मदद करते हैं, जिससे शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही अपने वाहनों पर वैध नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

नवीन कानून संबंधी अप्रशिक्षित आरक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। नए कानून संहिता के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला, रक्षित केंन्द्र राजनांदगांव के मंगल भवन में आयोजित किया गया। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर द्वारा अप्रशिक्षित आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई।

कार्यशाला में जिले के 370 से अधिक अप्रशिक्षित आरक्षक उपस्थित थे। दिनांक 19.06.2025 को एक दिवसीय कार्यशाला आ आयोजन रक्षित केन्द्र राजनांदगांव के मंगल भवन में आयोजित किया गया। जिसमें पुलिस

अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर द्वारा नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय पर 370 से अधिक अप्रशिक्षित आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि आरक्षक आम नागरिकों और कानून व्यवस्था के बीच पहला संपर्क होते हैं, अत: उन्हें नवीन कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आरक्षक को यह समझना जरूरी है कि नई प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना है (जैसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का सुरक्षित संग्रहण)। आम नागरिकों को भी नए कानूनों की जानकारी देना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसमें आरक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। नवीन कानूनों में नागरिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसे समझकर आरक्षक संवेदनशीलता के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरक्षकों के ज्ञानवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिससे वे नवीन विधानों के अनुरूप अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने अपेक्षा जताई कि सभी इन कानूनों की गहराई से जानकारी लेकर इसे अपने व्यवहार में लायेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर द्वारा इस अवसर पर कहा कि कानूनों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण आरक्षकों निरंतर अद्यतन रहना आवश्यक है, ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें। इस तरह के प्रशिक्षण सत्र न केवल दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं। उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने के लिए समस्त अप्रशिक्षित आरक्षकों को प्रेरित किया।

जिले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत 49 प्रकरण दर्ज, 231 किलो से अधिक गांजा बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला स्तरीय समिति नारकोटिक्स की बैठक जिले के प्रभारी सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग और वन विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में सुब्रत साहू ने पुलिस अधीक्षक से 01 जनवरी 2025 से 19 जून 2025 तक नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी ली।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 49 प्रकरण दर्ज किए गए और विभिन्न मादक पदार्थों, जैसे- गांजा 231.745 कि.ग्रा., नशीली दवाइयाँ 55182 नग, हेरोइन 306.29 ग्राम, ब्राउन शुगर 2.5 ग्राम की बरामदगी हुई है। साथ ही कोटपा एक्ट के तहत दो स्थानों पर कार्रवाई की गई है। उक्त 49 प्रकरणों में 2 प्रकरण पेट्रोलिंग/चेकिंग के दौरान एवं शेष 47 प्रकरण में मुखबीर की सूचना के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। मादक पदार्थ नष्ट करने हेतु तैयार 53 प्रकरणों की सूची तैयार की गई है। प्रभारी सचिव साहू ने निर्देश दिए कि जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण तीन से चार महीने में अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने नारकोटिक्स एक्ट के मामलों के शीघ्र निपटारे और जब्ती की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के लिए विशेष नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता जताई। इस पर साहू ने जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में महिला नशा पीड़ित, अवयस्क नशा पीड़ित और बाल नशा पीड़ितों के लिए पृथक-पृथक पुर्नवास व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच औषधि विक्रय में अनियमितताएँ पाई गईं।

इस पर 26 फर्मों को नोटिस, 18 के विरुद्ध निलंबन तथा 03 फर्मों के पंजीयन निरस्त किए गए। साहू ने अधिक से अधिक फर्मों के निरीक्षण और बंद फर्मों का पंजीयन समाप्त करने के निर्देश दिए।

नाम परिवर्तन

मैं नन्ददेव पिता श्री रामदेव निवासी 54/ए. स्ट्रीट एवेन्यू एवेन्यू ए सेक्टर 07. सिविक सेंटर भिलाई तह व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। यह कि मेरे स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक ब्रांच सेक्टर 10 भिलाई में खाता है। जिसका खाता नंबर 32220248052 है जिसमे मेरा नाम NAND DEV GUPTA है। यह कि मेरे आधार कार्ड नं. 7644 9470 8919 व पैन कार्ड नंबर APKPN7134H मे मेरा नाम NANDDEV अंकित है। जो कि सही व सत्य है। यह कि NAND DEV GUPTA व NANDDEV ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो कि मैं स्वयं हूँ तथा भविष्य में मैं अपने सही नाम NANDDEV से जाना व पहचाना जाता हूँ। अत: समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम NANDDEV से जाना व पहचाना जावें।

नन्ददेव (NANDDEV)
54/ए. स्ट्रीट एवेन्यू एवेन्यू ए सेक्टर 07. सिविक सेंटर भिलाई

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय अधीक्षण अभियंता
शिवनाथ मण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 169987/निविदा सूचना क्र. 02/वलेलि/2025-26, डोंगरगांव, दिनांक 18.06.2025

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 09.07.2025 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नाम :- राजनांदगांव (वर्तमान मोहला- मानपुर- अम्बागढ़ चौकी) जिले के विकासखण्ड मोहला की देवरसुर जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के आर.डी. 0 मी. से 3300 मी. तक रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य तथा 03 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण, 06 नग पक्के संरचनाओं का मरम्मत कार्य.

अनुमानित लागत :- रु. 170.25 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 25.06.2025 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है.

नोट: निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/ पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है.

जी- 252601649/9

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव
कृते- अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शारदाधाम पर्यटन स्थलों की सूची में हुआ शामिल

पर्यटन बोर्ड प्रचार प्रसार और सुविधा विकसित करने में देगा सहयोग, श्रद्धा और ज्ञान का अनोखा संगम है शारदाधाम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदाधाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ टुरीज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन बोर्ड ने इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया है। बोर्ड के इस निर्णय से इस पर्यटन स्थल को एक नई पहचान मिल सकेगी। बोर्ड इसके प्रचार-प्रसार के साथ ही पर्यटको के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए बजट उपलब्ध करा सकेगा।

श्रद्धा और ज्ञान का संगम है शारदाधाम

शारदाधाम में विद्यादायनी माँ सरस्वती की श्रद्धा और ज्ञान अर्जन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के जरूरतमंद बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। शारदाधाम समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इस विशेष कोचिंग संस्था में बच्चों के रहने,खाने के साथ उनकी कोचिंग की निशुल्क व्यवस्था की गई है। बच्चों के रहने और कोचिंग का जो भी खर्चा होता है,उसका व्यय समिति श्रद्धालुओं के सहयोग से पूरा करती है।

प्रकृतिक सौंदर्य से भरपूर है शारदाधाम प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल शारदाधाम,जिला मुख्यालय जशपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर,दुलदुला ब्लाक में स्थित है। माता सरस्वती का यह प्रसिद्ध मंदिर चारो ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। नजदीक ही गिरमा नदी की कलकल करती मधुर ध्वनि यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि विद्यादायनी मां सरस्वती का यह भव्य मंदिर पूरी तरह से श्रमदान से तैयार किया गया है। दोनों राज्यों के श्रद्धालुओं ने पसीना बहा कर मां के इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर के भवन का डिजाइन झारखंड के प्रसिद्ध लचलागढ़ हनुमान मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है।

पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है जशपुर

उल्लेखनीय है कि वनाँचल क्षेत्र जशपुर में पर्यटन उद्योग विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेजी से काम कर रहे हैं। कुनकुरी ब्लाक में स्थित मयाली नेचर कैंप के विकास के लिए दस करोड़ रूपये भारत दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। यहीं स्थित मधेश्वर महादेव को हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड ने विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने जिले को पर्यटन नक्शे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फ़रसाबहार ब्लाक में स्थित कोतेबीराधाम में लक्ष्मण झूला के तर्ज पर पुल निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही जिले में देशदेखा,रानीदाह जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय का लक्ष्य जिले में ग्रीन उद्योग विकसित कर जिलेवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री साय को बस्तर के ऐतिहासिक 'गोंचा महापर्व' का आमंत्रण: 'तुपकी' भेंट कर किया गया सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज रात्रि उनके निवास परिसर में जगदलपुर विधायक किरण देव के नेतृत्व में गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित गोंचा महापर्व में सम्मिलित होने का न्यौता दिया। उन्होंने बताया कि छह सौ वर्षों से अधिक समय से निरंतर मनाया जा रहा यह पर्व बस्तर में सामाजिक समरसता और प्रेम का प्रतीक है।

बस्तर दशहरा के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत चंदन यात्रा के साथ 11 जून से हो चुकी है। प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि पर्व के अंतर्गत 26 जून को नेत्रोत्सव पूजा तथा 27 जून को श्री गोंचा रथयात्रा का आयोजन होगा। 5 जुलाई को बाहुड़ा गोंचा रथयात्रा के साथ महापर्व का समापन होगा।

इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री साय को बस्तर की परंपरा अनुसार 'तुपकी' भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि गोंचा महापर्व में तुपकी चलाने की सदियों पुरानी परंपरा है। बस्तर के आदिवासी पोली बांस की नली से तुपकी तैयार करते हैं, जिसमें एक विशेष पौधे का फल डालकर बलपूर्वक दबाया जाता है, जिससे पटाखे जैसी आवाज उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए गोंचा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

प्रतिनिधि मंडल में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डे, गोंचा समिति अध्यक्ष चिंतामणि पाण्डे सहित हेमंत पाण्डे, रजनीश पाणिग्राही, नरेंद्र पाणिग्राही, सुदर्शन पाणिग्राही, पुरुषोत्तम जोशी, मुक्तेश्वर पांडे, बनमाली पाणिग्राही, दिनेश पाणिग्राही, दिलेश्वर पाण्डे, प्रशांत पाणिग्राही, देवशंकर पंडा, विजय पांडे, आत्माराम जोशी, देवकृष्ण पाणिग्राही, जयप्रकाश पाढ़ी, वैभव पाण्डे, चुम्मन पांडे, सोमप्रकाश जोशी, वेणुधर पाणिग्राही, प्रदीप पाढ़ी, सोमेश जोशी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने बेमेतरा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक

टेमरी में संचालित योजनाओं की जानकारी ली

श्रीकंचनपथ न्यूज

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका दो दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुँचे। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल डेका ने सर्किट हाउस स्थित सभाकक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नवागढ़ विकासखंड के उनके द्वारा गोद लिए गए ग्राम टेमरी में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में उन्होंने शिक्षाए स्वास्थ्यए पेयजलए कृषिए उद्यानिकीए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की जानकारी की।

राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि टेमरी गांव में जैविक भिण्डी की खेती की संभावनाएँ बेहतर हैं। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बाड़ी में जैविक भिण्डी का उत्पादन करें। उद्यानिकी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि ग्राम टेमरी का वातावरण भिण्डी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि गोद लिए गए ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचेए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत के सी ई ओ को निर्देशित किया कि ग्राम विकास की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा मिशन मोड में कार्य कर ग्राम को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।

बैठक के दौरान राज्यपाल को गांव में तीन तपेदिक ;टीण्बीण्द्ध रोगियों की जानकारी दी गईए जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छह माह की दवा हेतु आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त श्री डेका ने आठ मेधावी विद्यार्थियों को 5.5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। राज्यपाल ने श्रीराम बुनकर सहकारी समिति देवरबीजा के सदस्यों से भेंट की और उनकी भवन मरम्मत व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता2025 में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समापन पर राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया।

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से सुदूर वनांचल तक पहुंची योजनाओं की रोशनी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासन द्वारा शुरू किए गए 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' ने सुदूर वनांचल के बैगा समुदाय के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई है। शासन की योजनाएं अब पहले से कहीं अधिक सहजता से अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के दुर्गम ग्राम महामाई में आयोजित शिविर ने दुर्गाबाई बैगा जैसे कई परिवारों की जिंदगी को नई दिशा दी है। पहले जहां दुर्गाबाई को परिवार की चिकित्सा जरूरतों के लिए चिंता करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें और उनके परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इस शिविर में दुर्गाबाई के साथ उनके पति और तीनों बच्चे कुलदीप, राजमती और राममति सभी का आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बन गया।

दुर्गाबाई बैगा ने भावुक होकर बताया कि पहले हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं होने से इलाज कराने की चिंता हमेशा बनी रहती थी।

दुर्गाबाई बैगा को मिला आयुष्मान कार्ड, परिवार को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा की नई उम्मीद

अब हमारे पूरे परिवार को चिन्हांकित अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब पहली बार योजनाओं का लाभ इतनी सहजता से, बिना भागदौड़ के, गांव में ही मिल पाया है। इस अभियान के तहत जिले के बैगा बाहुल्य गांवों में लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रशासन जन सेवा आपके द्वार की भावना से कार्य कर रहा है, जिससे शासन की योजनाएं सही अर्थों में जन-जन तक पहुंच रही हैं।

जीवन में आई नई उमंग, जब मिला प्रधानमंत्री आवास

आवास की दीवारों पर जनजाति कलाकृतियां वाद्य यंत्र, नृत्य एवं अन्य आर्ट से सजाया सपनों का घर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जब सहोद्रा बाई धनवार को अपने घर की चाबी मिली, तो यह महज चाबी नहीं थी यह उनके आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की शुरुआत थी। जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम पंचायत पुछेली खपरीडीह में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के दौरान जब श्रीमती सहोद्रा बाई धनवार को मंच से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के घर की चाबी सौंपी गई, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी।

उन्होंने मुस्कराते हुए सहजता से कहा, चाबी तो दे दी आपने, लेकिन ताला नहीं दिया। उनकी यह मासूम बात सुनकर पूरा वातावरण मुस्कान और भावनाओं से भर गया। यह क्षण न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गाँव के लिए गर्व और खुशी का था।

श्रीमती सहोद्रा बाई ग्राम पंचायत खपरीडीह के जीवन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने खुशियाँ भर दी हैं। पाँच वर्ष पहले उनके पति का निधन हो गया था। उनकी तीन बेटियां और चार बच्चे है। जिनकी शादी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के साथ-साथ उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन, पेंशन योजना और मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी जैसे योजनाओं का लाभ पाकर उनका जीवन सशक्त और आत्मनिर्भर बन गया है।

जनजातीय कलाकृति से सजा सपनों का घर

प्रधानमंत्री आवास योजना से बने उनके नए घर में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, वाद्य यंत्र, पारंपरिक नृत्य, और अन्य पारंपरिक लोककला से जुड़ी चित्रकारी को घर की दीवारों पर उकेरकर एक जीवंत संस्कृति का प्रतीक बना दिया है। उनका यह प्रयास न केवल कलात्मक है, बल्कि अब वह अन्य ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। उनके घर की सजावट पूरे जनपद पंचायत में चर्चा का विषय है और जनजातीय पहचान की झलक को दिखा रहा है। श्रीमती सहोद्रा बाई ने अपने घर के सामने एक पेड़ मां के नाम आम के पौधा लगाया है। वहीं उन्होंने जल सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने घर में सोखता गड्ढा का भी निर्माण किया है। आवास योजना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से फुलेश्वर के पक्के मकान का सपना हुआ सच

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ धमतरी जिले के कमार समुदाय के लोगों को सीधा-सीधा मिल रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत धमतरी जिले के दूरस्थ वनांचल नगरी के कल्लेमेटा के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय कमार वर्ग के हितग्राही फुलेश्वर के खुद के पक्के आशियाने का सपना साकार हुआ है। फुलेश्वर ने आवास पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 में उन्हें आवास की मंजूरी मिली। पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही घर बनाने का काम शुरू किया गया। इसमें पहली किश्त के तौर पर 40 हजार रुपये मिलते ही उनका मकान बनने की उम्मीद पक्की होने लगी। आधार पर क्रमशः दूसरी किश्त 60 हजार रूपये, तीसरी किश्त 80 हजार रूपये और चौथी किश्त 20 हजार रूपये की राशि मिलती गई।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950